सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 283, नई दिल्ली | रविवार, 24 दिसम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

ऊँचाई पर वही पहुँचते है,
जो बदला नहीं बदलाव
लाने की सोच रखते है।

राजधानी की सड़कों पर काल बनकर दौड़ रहीं डीटीसी-क्लस्टर बसें, 5 साल में ली 278 की जान

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों से लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले पांच सालों में इन हादसों में 278 लोगों की जान गई। सरकार और परिवहन विभाग ने काफी कदम उठाए हैं।

संजय बाटला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही डीटीसी और क्लस्टर बसों से लगातार हादसे हो रहे है। कई बार हम देखते हैं कि तेज गति के कारण बस बेकाबू होकर बड़े हादसे का कारण बन जाती हैं। आंकड़े भी बता रहे हैं कि बसों से लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते पांच से छह वर्षों के अंदर बसों से 812 हादसे हुए हैं, जिसमें 278 लोगों की जान गई। बीते दिनों दिल्ली विधान सभा में एक सवाल के जवाब में यह आंकड़े सरकार के तरफ से रखे गए। हादसों को रोकने की दिशा में सरकार और परिवहन विभाग की तरफ से कई अहम कदम भी उठाए जा रहे है।

परिवहन विभाग का कहना है कि एक अप्रैल 2022 से बस लेन ड्राइव को अनिवार्य किया गया, जिसके तहत बस लेन ड्राइविंग पर नजर रखने के लिए राजधानी में 100 टीमें भी तैनात की गई लेकिन अक्सर देखा गया है कि चुनिंदा सड़कों पर बस लेन ड्राइविंग का पालन होता है, लेकिन बाहरी दिल्ली में मुख्य लेन पर बसें दौड़ती मिल जाएगी। बस लेन ड्राइव के तहत परिवहन विभाग ने राजधानी की तरफ 74 सड़कों पर करीब छह सौ किलोमीटर लंबे हिस्से को बस लेन ड्राइव के तौर पर चिन्हित किया गया।

इसमें तय किया गया कि बसें डिवाइडर की साइड वाली लेन में न चलकर फुटपाथ वाली साइड में चलेंगी, जिससे कि बस स्टॉपेज पर बस को रोकने में आसानी हो। क्योंकि कई बार देखा गया कि हादसे के पीछे की एक वजह यह भी थी कि अचानक से बस डिवाइड किनारे की लेन से बस स्टॉपेज पर रुकने के लिए फुटपाथ किनारे की लेन में आती थी, जिसके वजह से हादसे होते थे। इसके साथ ही विभाग ने 5490 बस चालकों के चालान भी काटे हैं लेकिन उसके बाद भी सड़क हादसों में कोई व्यापक सुधार नहीं आता है। उल्टे डीटीसी बसों से होने वाले हादसे वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में काफी बढ़ गए। 2021 में 84 बस हादसे हुए जबकि वर्ष 2022 में 120 सड़क हादसे हुए।

क्लस्टर बसों से हादसे

वर्ष	दुर्घटना	मौतें
2019-20	32	20
2020-21	28	26
2021-22	37	36
2022-23	55	31
2023-23 अब तक	55	18

वर्तमान में कुल बसों की संख्या
डीटीसी- 4391
क्लस्टर- 2841

राम मंदिर: प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या के लिए उड़ेंगे 100 विमान, हवाई अड्डे के अलावा बनाए गए तीन हेलीपैड

चार्टर्ड प्लेन की संख्या बढ़ी तो उन्हें इन तीन शहरों के हेलीपैड पर उतरवाने का बंदोबस्त कर मेहमानों को सड़क मार्ग से रामजन्मभूमि तक लाने का प्रबंध किया जाएगा।

लखनऊ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को बड़ी संख्या में विशिष्ट मेहमान चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। इस दिन 100 से ज्यादा विमान रामनगरी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अब तक बनाए गए तीन हेलीपैड पर इन्हें उतारे जाने में समस्या आ सकती है। इसके लिए प्रशासन ने वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी वैकल्पिक इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं।

चार्टर्ड प्लेन की संख्या बढ़ी तो उन्हें इन तीन शहरों के हेलीपैड पर उतरवाने का बंदोबस्त कर मेहमानों को सड़क मार्ग से रामजन्मभूमि तक लाने का प्रबंध किया जाएगा। कमिश्नर गौरव दयाल ने शनिवार को बताया कि इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से समन्वय कर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां समीक्षा बैठक में बताया था कि करीब 100 विमान 22 जनवरी को आ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

लखनऊ से अयोध्या के लिए चलेंगी 50 स्पेशल बसें

अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ से 50 और स्पेशल बसें अयोध्या के लिए चलाएगा। इससे रूट पर कुल बसों की संख्या 150 हो जाएगी। लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि इस रूट पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। विभिन्न रूटों पर संचालित बसों को भी जरूरत के अनुसार अयोध्या रूट पर लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इस रूट पर कम से कम 50 बसें और चलाई जाएंगी।

नये साल पर डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें

नए साल पर दिल्ली वालों को 200 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। यह बसें जनवरी में क्लस्टर बसों के बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों के आ जाने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1500 हो जाएगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नए साल पर दिल्ली वालों को 200 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। यह बसें जनवरी में क्लस्टर बसों के बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों के आ जाने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1500 हो जाएगी। अभी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में 1,300 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिनमें से 500 बसों को इसी महीने की शुरुआत में हरी झंडी दिखाई गई थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्लस्टर बसों को दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) निगरानी और प्रबंधन करता है।

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि क्लस्टर बसों के बेडे में 3000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में आईएमटीएस के पास 3,043 क्लस्टर बसें हैं, जिनमें से 2,841 संचालित हैं। पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है और अब तक 682 बसें सड़कों से हट चुकी हैं। इन बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 अंत तक दिल्ली में कुल बसों की संख्या 10,480 की जाएगी। इसमें 80 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसे पूरा करने के लिए 6,000 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हर महीने बेड़े में 50 से 100 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी।

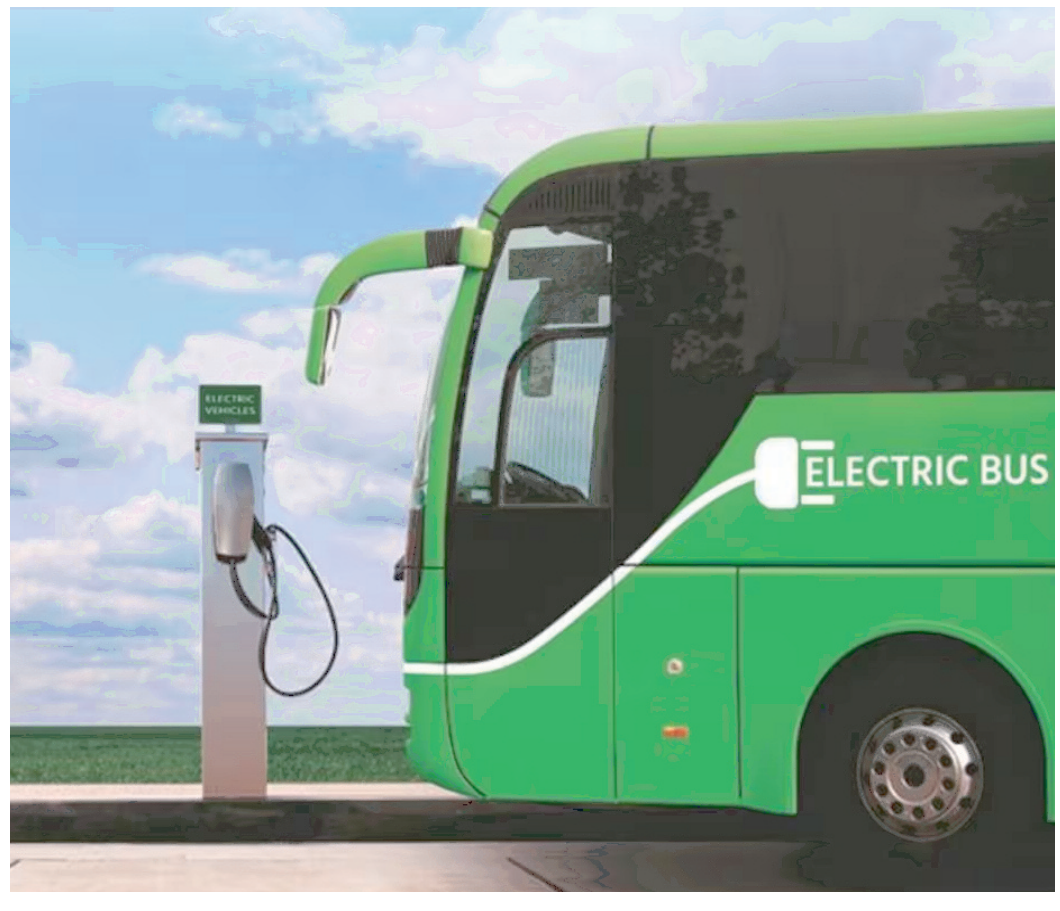

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पाइनव्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
भारत सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैप डीलर (आरवीएस)

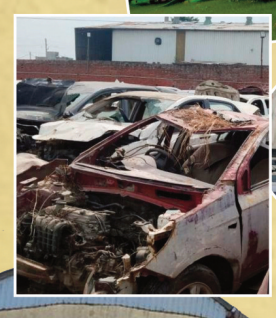

- हरियाणा राज्य में प्रतिदिन 100 वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता के साथ 3 एकड़ का स्क्रैपिंग यार्ड
- दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और दिल्ली परिवहन विभाग के साथ मिलकर ईएलवी वाहनो को हटाने और कायदे अनुसार स्क्रैप करने में सहयोग और योगदान
- दिल्ली सरकार द्वारा उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली द्वितीय कंपनी
- जनता द्वारा स्वेच्छा से अपने ईएलवी वाहन को उचित मूल्य दर प्रदान कर स्क्रैप करने में अव्वल,
- डी टी सी की 100 ईएलवी बसों को स्क्रैप करने का टेंडर प्राप्त करने वाली कम्पनी
- आर .वी .एस .एफ . की नवीनतम नीति के अंतर्गत हरियाणा में लाइसेंस प्राप्त करने वाली तृतीय कंपनी
- कंपनी का दृष्टिकोण और ईएलवी वाहनों को स्क्रैप करने की कार्यशैली पूर्ण रूप से पर्यावरण स्वरूप

पाइनवियो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
(भारत सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैप डीलर)
मुख्य स्क्रैप सेंटर
विक्रम बख्शी :- 09999996391
यूनिट एवम कार्यालय :- 63, पिआयू मनियारी, नरेला रोड कुंडली, सोनीपत, हरियाणा 131001
दिल्ली में मिलने का कार्यालय :-
अनिल :- 08178234951
खजान बस्ती गुरद्वारे के करीब,
ग्राउंड फ्लोर, सी :-260 - लेफ्ट साइड हिस्से में, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, न्यू दिल्ली 110064 .

इनसाइड

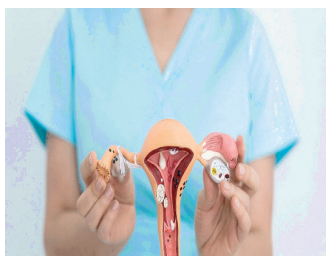

फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं !

महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म

जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती हैं. यही नहीं, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोकें

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए'

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों मे छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीड़न कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता या गाली गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस जानकारी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्याकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानवता से नफरत करने लगता है। उसे हर व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना होता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाली स्थिति होती है। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। यौन उत्पीड़न के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीड़न के थे। उत्पीड़न के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकड़ने का था। उत्पीड़न के प्रत्येक पांच मामलों में से एक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने या कॉल या लिखित वॉट्सऐप मैसेजों के जरिए उत्पीड़न का था।

जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा ऑडिट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों में करवाया जाना चाहिए। सच बोलें तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। उन्हें हर कदम पर न जाने कितनी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफिस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां घर तक पर सेफ नहीं हैं। आए दिन पिता या भाई द्वारा भी रेप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उत्पीड़न की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तदर्थ महिला अध्यापकों को भी पक्की जॉब के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीड़न किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कर्मचारियों को विद्यार्थियों पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियों और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक ज़माने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहें जिससे छात्राओं के यौन शोषण के मामले दबे नहीं।

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें, क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उत्साह देने के लिए उन्हें सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए कितने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप क्यों कमरे में आईं या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूंढती रहीं? अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस्या नहीं है. दरअसल इस समस्या को मॉमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश्त क्षमता पर स्थाई असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

मॉमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक स्ट्रा प्लान बनाएं तो मॉमी ब्रेन की समस्या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की व्यस्तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

ज्यादा वजन भी बन सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह, इन तरीकों से करें बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के खतरे से खुद को बचाना है तो समय-समय पर अपनी जांच जरूर कराती रहें. इसके अलावा, जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहें, भरपूर आराम करें और रोजाना योग जरूर करें. इन बातों का ध्यान रखकर आप इस खतरे से बच सकती हैं.

मां बनने का सपना हर महिला देखती है. लेकिन कई महिलाओं में सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से उनकी प्रेगनेंसी कठिनायों से भरी होती है. कई बार तो उनके लिए प्रेगनेंसी जोखिम भरा हो जाता है और इससे मां और पेट में पल रहे बच्चे की जान तक जा सकती है. इसी जोखिम को 'हाई रिस्क प्रेगनेंसी' कहा जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन 5,29,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान इन खतरों की वजह से हो जाती है. इसकी वजह खराब सेहत, बदलती लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाही को माना जाता है. यही नहीं, कई बार ऐसी समस्याएं किसी बीमारी या जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ये हैं बड़ी वजह

एनआईएच के मुताबिक अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे प्रेगनेंसी में रिस्क की समस्या हो सकती है. अगर महिला का वजन ज्यादा है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, गर्भकालीन मधुमेह, स्टिलबर्थ, न्यूरल ट्यूब दोष और सिजेरियन डिलीवरी की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से जन्म के समय नवजात में हृदय रोग का खतरा 15% तक बढ़ सकता है.

किशोरावस्था और 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था की वजह से प्रीक्लेम्पसिया और गर्भकालीन उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह बन सकता है. गर्भाशय में हुई कोई पुरानी सर्जरी की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, जुड़वा बच्चों और आईवीएफ द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया भी महिलाओं में रिस्की प्रेगनेंसी की वजह हो सकता है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचाव का तरीका

अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो समय-समय पर अपनी जांच कराती रहें. इसके अलावा, प्रेगनेंसी में तनाव से बचें, भरपूर आराम करें, रोजाना योग ध्यान करें, फ्रेश हवा में वॉक पर जाएं, हेल्दी खान पान करें और डॉक्टर की संपर्क में रहें.

एलजी का आदेश :- अब दिल्ली वाले घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत, जानें कैसे ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए. तकनीकी के इस दौर में घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से सारी सुविधाएं उपलब्ध है. ऐसे में लोगों की समस्याओं के निवारण और शिकायतों के लिए भी अब पोर्टल और एप्स शुरू किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब दिल्लीवासियों को आने वाले समय के भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पडेगी. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आम जन घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अब भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे.

शिकायत के साथ भेज सकेंगे फोटो/ विडियो

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और विभिन्न विभागों के मुख्त सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके निर्देश पर देश में पहली बार भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ओ सी आई एम एस) तैयार किया जा रहा है. एनआईसी द्वारा तैयार किए जा रहे इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के साथ फोटो, वीडियो और ऑडियो भी भेज सकेंगे. बैठक में उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में

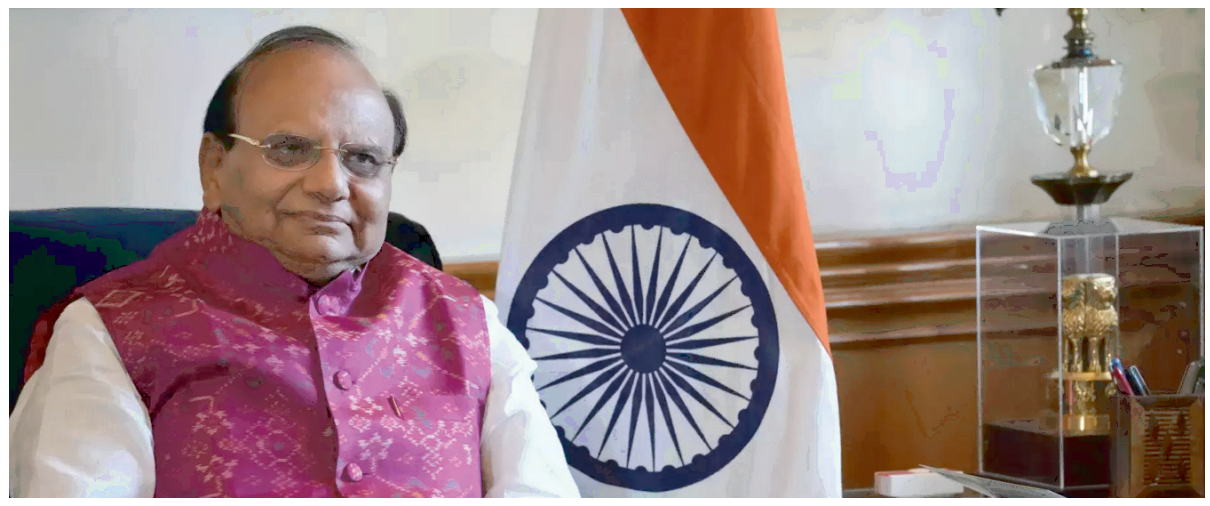

औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए. एलजी के इस आदेश के बाद से दिल्ली के अलग-अलग विभागों में कार्यरत अधिकारी सकते में हैं. ऐसा इसलिए कि अब लोग अपनी शिकायत सीधे एलजी तक पहुंचा पाएंगे.

साक्ष्य के साथ ई-एफिडेविट देना अनिवार्य

उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस पोर्टल पर शिकायत का संतुलन बनाने के बंदोबस्त करें. एक तरफ जहां भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिले तो वहीं दूसरी तरफ झूठी शिकायतों से किसी अधिकारियों को नाहक परेशानी न झेलनी पड़े. इसके लिए उन्होंने शिकायत के साथ साक्ष्य अपलोड को अनिवार्य करने की सलाह दी है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को अपना आधार नंबर और दी गई जानकारी की सत्यता से संबंधित एक ई-एफिडेविट भी देना होगा.

दारू के बाद दवा खरीद में सीबीआई जांच के आदेश

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कथित शराब घोटाला मामले में आप नेताओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब एक और गंभीर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है। ये आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए हैं। अब ये मामला सरकारी अस्पताल में दवा खरीद से जुडा हुआ है।जिसमें तमाम कायदे-कानूनों को ताक पर रखने के आरोप लगाए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं में गडबडी पा ए जाने के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इन अस्पतालों ने दवाई खरीदने में लापरवाही बरती और ये सरकारी और प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के फेल पाई गई है।सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इन दवाओ को लेकर विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।इसके साथ ही चीफ सेकेट्ररी नरेश कुमार को भी लेटर लिखकर जांच करने को कहा है। बताया जा रहा है कि इन दवाओ की जब सरकारी और प्राइवेट लैब में जांच की गई तो तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। जिसके बाद जांच के आदेश दिए है। लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार एक बार फिर मुश्किलों में पडती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर निशाना साधा। कहा ,सीएम केजरीवाल का सब कुछ नकली है।नकली व्यक्तित्व नकली दवांए । असली है तो बस भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। उल्लेखनीय है कि कथित शराब घोटाला मामले में भी डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढाई गई है। सीएम केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन भेजा गया है इसमें उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। दो बार के समन की पेशी पर वह अटेंड नहीं कर पाए।

खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई, कई गुना जहरीली हुई हवा; जानें अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह धुंध (स्मॉग) छाई रही और दृश्यता भी कम रही। सुबह साढ़े दस बजे गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज किया गया। हवा नहीं चलने और तापमान में गिरावट आने के कारण स्मॉग छा रहा है। ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद भी शहर में निर्माण कार्य चल रहे हैं।

गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह धुंध (स्मॉग) छाई रही और दृश्यता भी कम रही। सुबह साढ़े दस बजे गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज किया गया। हवा नहीं चलने और तापमान में गिरावट आने के कारण स्मॉग छा रहा है। ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद भी शहर में निर्माण कार्य चल रहे हैं। हालांकि निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है।

विभागों की ओर से प्रदूषण की रोकथाम के लिए दमकल की गाड़ियों और टैंकरों से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन यह उपाय ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। मौसम बदलने, हवा चलने या फिर वर्षा होने के बाद ही स्मॉग छंट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है। शनिवार को दिनभर आंशिक बादल छाए रहे। मौसम परिवर्तनशील रहने के कारण दिन के तापमान

में गिरावट तथा रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।

कहां कितना एक्यूआई रहा (पीएम 2.5)

सेक्टर 51 - 364
ग्वाल पहाड़ी - 404
विकास सदन - 311
टेरी ग्राम - 426
(एचएसपीसीबी के प्रदूषण मापक यंत्रों से सुबह 10:30 बजे लिए गए आंकड़े)

प्रदूषण बढ़ने के यह है कारण

टूटी सड़कों से उड़ रही धूल
खुले में कचरा जलाना
सड़कों के किनारे लगे मलबे के ढेर

शहर के चौराहों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम

इन सड़कों पर लग रहे ट्रैफिक जाम

शहर में ओल्ड दिल्ली रोड, महरौली रोड, ओल्ड रेलवे रोड, बस स्टैंड रोड, न्यू रेलवे रोड, महावीर चौक, सोहना रोड, एमजी रोड, सुभाष चौक, सदर बाजार, खांडसा रोड, पटौदी रोड, उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक रोड, सेक्टर 34, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, नेता जी सुभाष मार्ग और मिलेनियम सिटी सेंटर तथा इफको चौक रोड पर दिनभर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। इसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है।

बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई होगी।

- विजय चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा

दो शख्स ने बाइक सवार युवक को पहले कहा नमस्ते, फिर मारा चाकू; पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात बाइक पर दोस्त के साथ घर जा रहे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। युवक को चाकू मारने वाला उसका परिचित है। दोनों में कुछ समय पहले किसी बात पर विवाद हुआ था। बृहस्पतिवार देर रात दोनों ने आपस में एक दूसरे को नमस्ते किया। फिर आरोपित ने चाकू मार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात बाइक पर दोस्त के साथ घर जा रहे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। युवक को चाकू मारने वाला उसका परिचित है। दोनों में कुछ समय पहले किसी बात पर विवाद हुआ था। बृहस्पतिवार देर रात दोनों ने आपस में एक दूसरे को नमस्ते किया। फिर आरोपित ने चाकू मार दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपित गिरफ्तार किए हैं।

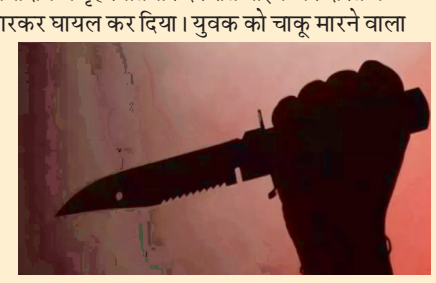

बहरामपुर में रहने वाले राजा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिस्त्री का काम करते हैं। बृहस्पतिवार देर रात वह अपने दोस्त सचिन के साथ चार मूर्ति की तरफ से घर जा रहे थे। मुखिया फार्म हाउस के पास उन्हें रिंकू पुत्र इंदर और अरुण पुत्र अशोक मिले। राजा को रोक दोनों ने नमस्ते किया फिर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल राजा जमीन पर गिर गए इसी बीच आरोपित फरार हो गए।

नमस्ते कहने के बाद मारा चाकू

राजा की पत्नी रेनू का कहना है कि पहले दोनों हमलावरों ने नमस्ते किया था। उसके बाद चाकू से वार कर दिए। उनके पति को पहले जिला एमएमजी अस्पताल भर्ती कराया गया उसके बाद जीटीबी रेफर किया गया। शुक्रवार को उनके पति घर आ गए। इस मामले में एसीपी वेव सिटी सलोनी अग्रवाल का कहना है घायल की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों आरोपित गिरफ्तार कर लिये गए हैं।

'संसद की सेंधमारी में कोई राजनीतिक दल या अन्य संगठन तो शामिल नहीं', आरोपितों का नार्को एनालिसिस करा सकती दिल्ली पुलिस

जांच एजेंसियां यह जांच कर रही है कि संसद की सुरक्षा चूक मामले के पीछे कहीं किसी राजनीतिक पार्टी अथवा अन्य संगठनों के हाथ तो नहीं है? हर संभावित पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। अबतक की जांच से किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के कारण दिल्ली पुलिस सभी आरोपितों का साइको एनालिसिस जांच और नार्को एनालिसिस जांच कराने पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार किए सभी छह आरोपित सागर शर्मा, मनोरंजन गौड़, अमोल शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा व महेश कुमावत से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलीजेंस, आईबी व रॉ पिछले 11 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है।

इनसे अलग-अलग और साथ बैठाकर भी गहन पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि संसद भवन के अंदर व बाहर कलर स्मोक क्रैकर चलाने व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कड़ा विरोध जमाने के पीछे इनका मकसद क्या था? इस घटना को अंजाम दिलाने के पीछे कहीं किसी राजनीतिक पार्टी अथवा अन्य संगठनों के हाथ तो नहीं है? हर संभावित पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। अबतक की जांच से किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के कारण दिल्ली पुलिस सभी आरोपितों का साइको एनालिसिस जांच और नार्को एनालिसिस जांच कराने पर विचार कर रही है।

कोर्ट की अनुमति के बाद होगा नार्को

सूत्रों के मुताबिक पहले सभी आरोपितों का पुलिस रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में साइको एनालिसिस जांच करा सकती है। इसके लिए सभी की फीजिशियन डॉक्टर से स्वास्थ्य की जांच कराई गई है। इसके बाद अहमदाबाद में सभी का नार्को एनालिसिस जांच कराई जा सकती है। इसके लिए पहले कोर्ट ने अनुमति लेनी होगी। सभी आरोपितों की भी इस जांच के लिए सहमति लेगी। अगर आरोपित नार्को जांच के लिए तैयार नहीं होंगे तब यह जांच कराना मुश्किल हो सकता है।

महेश को 13 दिन की पुलिस रिमांड

शनिवार को छठे आरोपित महेश कुमावत के सात दिन का रिमांड खत्म हो जाने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश कर 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया गया। शुक्रवार को ललित झा का रिमांड खत्म हो जाने पर कोर्ट में पेश कर दोबारा 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया गया। तीन दिन पहले बृहस्पतिवार को चार आरोपित सागर शर्मा, मनोरंजन गौड़, अमोल शिंदे व नीलम आजार को दोबारा पटियाल हाउस कोर्ट में पेश कर 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया।

'घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता', कोरोना के नए सब-वेरिएंट JN.1 पर आया Delhi AIIMS का बयान

एम्स दिल्ली में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. निश्चल ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि इस प्रकार की लहरें आती रहेंगी। यहां तक कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी हमने भविष्यवाणी की थी कि इस वायरस के और अधिक बदलते स्वरूप हमारे सामने आएगा। यह ऐसा चरण होगा जहां यह अधिक संक्रामक हो जाएगा। इसमें मृत्यु दर या संक्रमित होने का रेट कम होगा।

नई दिल्ली। देश में कोविड 19 के नए सब-वेरिएंट जेएन.1 के मामलों में वृद्धि के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स में डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि देश के कई राज्यों में लोग COVID-JN.1 के नए सब-वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। मरीजों में इसके लक्षण हल्के हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है।

एम्स दिल्ली में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. निश्चल ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि इस प्रकार की लहरें आती रहेंगी। यहां तक कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी हमने भविष्यवाणी की थी कि इस वायरस के और अधिक बदलते स्वरूप हमारे सामने आएगा। यह ऐसा चरण होगा जहां यह अधिक संक्रामक हो जाएगा। इसमें मृत्यु दर या संक्रमित होने का रेट कम होगा।

डॉ. निश्चल ने कहा कि आप यह कह सकते हैं कि मनुष्यों और इस वायरस के बीच की लड़ाई है जो दोनों जीवित रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस सब वेरिएंट से संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन यह पहले के डेल्टा वेरिएंट जितना खतरा पैदा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस वायरस के बारे में अधिक जागरूक हैं और हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। इसलिए यदि आप मामलों को बढ़ोतरी देख रहे हैं तो यह दर्शाता है कि हमारी निगरानी प्रणाली सही जगह पर है।

'नया सब-वेरिएंट ओमीक्रॉन से बहुत अलग नहीं'

उन्होंने कहा कि जो नया संस्करण हमारे सामने आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सामने आ रहे केसेस यह दिखाता है कि हम अब कितनी अच्छी तरह तैयार हैं और मुझे लगता है कि हम इसे अच्छे तरीके से संभालने में सक्षम हैं। डॉ. नीरज ने आगे कहा कि जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, उससे पता चलता है कि नया सब-वेरिएंट ओमीक्रॉन से बहुत अलग नहीं है। हम देख रहे हैं कि क्या वायरस खांसी, सर्दी, छींकने, बुखार और शरीर में दर्द जैसे समान प्रकार के लक्षण पैदा कर रहा है या नहीं।

'सब-वेरिएंट पर हम निगरानी रखे हुए हैं'

डॉक्टर ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम इस बात की जांच कर रही है कि क्या सब-वेरिएंट फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है? क्या इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है या क्या इससे पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां इसके मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन इसे पूरे देश के लिए नहीं कह सकते हैं। यह अच्छी बात है कि हमारे पास एक बेहतर निगरानी प्रणाली है और हम इस बीमारी को रोक सकते हैं।

देखो राम आए हैं: आतंकियों से लिया लोहा तो विवादित ढांचा गिराने में रहे आगे जयभगवान गोयल

वीं दिल्ली के शाहदरा निवासी व राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभगवान गोयल ऐसे ही हैं। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा ढहाने के आरोप में उनपर कोई 28 साल तक मुकदमा चला। दो हफ्ते जेल में बिताए। कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे लेकिन कभी भी अपने संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। शाहदरा चौक में अपने कार्यालय में बातचीत में कहते हैं कि सब राम जी की कृपा है।

नई दिल्ली। ऐसे विरले ही होते हैं जो समाज पर हो रहे जुल्म का खुलकर प्रतिकार करें और दो-दो हाथ करें। जब मौका आए तो गुलामी और बर्बरता के प्रतीक को ढहाने में भी तनिक विचलित न हो। साथ ही बिना किसी डर-भय के, परिणाम तथा भविष्य की परवाह किए बगैर अपने कृत्य को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लें।

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा निवासी व राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभगवान गोयल ऐसे ही हैं। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा ढहाने के आरोप में उनपर कोई 28 साल तक मुकदमा चला। दो हफ्ते जेल में बिताए। कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे, लेकिन कभी भी अपने संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। शाहदरा चौक में अपने कार्यालय में बातचीत में कहते हैं कि सब राम जी की कृपा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व जिसके चलते अयोध्या में भव्य राममंदिर में रामलला के विराजमान होने का उनके साथ असंख्य लोगों का स्वप्न पूरा हो रहा है।

उन दिनों को याद करते हुए जय भगवान गोयल बताते हैं कि वह पंजाब से वर्ष 1986-87 में दिल्ली आ गए थे और उनकी मुलाकात शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से हुई। जिसके बाद दिल्ली में शिवसेना की इकाई गठित की। तब तक राम मंदिर का मुद्दा गर्माने लगा था। वह भी बैठकों में शामिल होने लगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा की आगवानी की। इसके साथ ही वर्ष 1990 की कारसेवा का मौका आया। घड़ी आ गई जब कार सेवा के लिए जत्थे के साथ ट्रेन से निकल पड़े, लेकिन टूंडला में उनके साथी पकड़े गए, लेकिन यह बच गए, क्योंकि इन्होंने सिख का वेश धारण किया था।

वहां से वह ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर प्रतापगढ़ तक पहुंचे, रास्ते में लोग हर तरह की सहायता करते मिले, लेकिन वहां आखिरकार हिरासत में ले लिया गया और अस्थाई जेल के रूप में निर्मित किए गए चिलबिला स्थित इंटर कालेज में बाकि कार सेवकों के साथ बंद कर दिया गया। वह बताते हैं कि वहां चंद पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि अस्थाई जेल में 500 लोग थे। ऐसे में कार सेवकों ने जोश भरा और पुलिसकर्मियों को धत्ता बताते हुए आगे बढ़ गए। रेल लाइन के किनारे-किनारे चलते हुए गांवों में रूकते हुए अयोध्या पहुंच गए। इस दौरान लोगों में रामभक्तों की सेवा का भाव जबरदस्त देखा।

मुलायम यादव के आदेश पर गोलियां बरसी

जब वह लोग अयोध्या पहुंचे तो वहां जन सैलाब था। निहत्थे कार सेवक आगे बढ़ रहे थे। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस उनपर गोलियां बरसा रही थी। देखते-देखते ही सड़कें लाशों से बिछ गई। सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया। असंख्य लोग मारे गए। मारे गए लोगों की गिनती न हो इसलिए पत्थर बांधकर उनके शव को सरयू में डाला जा रहा था। उनकी टोली ने तत्काल ही पिछले हटने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा वह मरने नहीं आए हैं। बल्कि यहां विवादित ढांचे पर राम ध्वजा लहराने आए हैं।

जबकि इधर, दिल्ली में यह अफवाह फैल गई थी जय भगवान गोयल और उनके साथी बलिदान हो गए हैं। इसके बाद जब वह लौटे तो उन्हें उत्तर भारत का शिवसेना प्रमुख बना दिया गया। राम जी की कृपा से संगठन की ताकत बढ़ने लगी। ऐसे में 92 के कारसेवा का दिन भी आया। उन लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार ढांचा टूटना ही है। दिल्ली में प्रेस कांफ्रेस कर इसका ऐलान भी किया कि कारसेवा शिवसेना स्टाइल में होगी।

शिवसैनिकों का जत्था अयोध्या पहुंचा

इस तरह पांच दिसंबर को शिवसैनिकों का जत्था अयोध्या पहुंचा। जत्था साथ में डायनामाइट भी ले गया था कि अगर कार सेवकों ने नहीं टूटा तो उसे उड़ा देंगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। 'गंगा की धार को मोड़ देंगे, ढांचा तोड़ देंगे' की लहर ने कार सेवकों को जोश से भर दिया। दो गुंबद तो टूट गया, लेकिन तीसरा ढांचा नहीं गिर रहा था। लोग तोड़ने की कोशिश में लहूलुहान हो रहे थे। फिर भी वह टूटा। उसके गिरते ही सभी मलबे और ईंट को उठा-उठाकर ले जाने लगे। देखते ही देखते पूरी जमीन समतल हो गई। कार सेवकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जय भगवान गोयल ने साथ लाए मिठाई का वितरण किया।

फिर अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही यह घोषणा कर दी कि शिवसैनिकों ने ढांचा तोड़ा है। इसके लिए उन्हें फांसी भी हो जाए तो फक्र है। इसके बाद तो घरों में तलाशी और पूछताछ का दौर चला। सीबीआइ ने गिरफ्तार किया। करीब दो हफ्ते जेल में रहे। मामले की सुनवाई लखनऊ की सीबीआई अदालत में चली। फिर सितंबर 2020 में निर्णय आया और बरी कर दिया गया।

हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया गया

पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकियों से लिया लोहा उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा के जिंद का है। बाद में वे लोग पंजाब के लुधियान में बस गए। वर्ष 81-82 में जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों ने वहां के हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया और उन्हें वहां से भगाया जाना शुरू हुआ तब जय भगवान युवा ही थे। उनसे यह पीड़ा देखी नहीं गई और कुछ लोगों के साथ हिंदू शिवसेना नामक संगठन बनाकर हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया। देखते ही देखते संगठन का स्तर बड़ा हो गया और इसका प्रतिकार भी दिखने लगा।

हिंदू शिवसेना के 74 लोगों को निशाना बनाया गया

यहां तक की वर्ष 1982 में अपने एक साथी की गिरफ्तारी पर उन्होंने पंजाब बंद का आह्वान कर दिया, जो बड़ा सफल रहा, लेकिन इसके बाद ये सभी आतंकियों के निशाने पर आ गए। हिंदू नेताओं को मारा जाने लगा। यहां तक की हिंदू-सिख एकजुटता की पैरोकारी करने वाले सिख नेताओं को भी आतंकी निशना बनाने लग गए। पूरा माहौल और दहशत भरा हो गया। जय भगवान गोयल बताते हैं कि उस दौरान हिंदू शिवसेना के 74 पदाधिकारियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इससे उनका परिवार भी दहशत में आ गया और उनके काफी दबाव डालने के बाद वह दिल्ली आ

भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े कराए 134 अवैध फ्लैट बनेंगे GDA अधिकारियों के गले की फांस, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

इंदिरापुरम स्थित एक्सप्रेस गार्डन सोसाइटी में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े कराए 134 अवैध फ्लैट प्राधिकरण अधिकारियों के गले की फांस बनेंगे। मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद से जीडीए अधिकारियों में हड़कंप है। जांच कर अवैध निर्माण कराने के दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी मामले की विस्तार से जांच करेगी।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित एक्सप्रेस गार्डन सोसाइटी में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े कराए 134 अवैध फ्लैट प्राधिकरण अधिकारियों के गले की फांस बनेंगे। मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद से जीडीए अधिकारियों में हड़कंप है। जांच कर अवैध निर्माण कराने के दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी मामले की विस्तार से जांच करेगी।

एक्सप्रेस गार्डन सोसाइटी बनाने के लिए बिल्डर ने वर्ष 2005 में जीडीए से 400 फ्लैटों का नक्शा स्वीकृत कराया। इसके बाद 536 फ्लैटों का संशोधित नक्शा जीडीए से स्वीकृत हुआ। वर्ष 2008-12 के बीच जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर ने नियमों को ठेंगे पर रखा और

536 की बजाय 670 फ्लैटों का निर्माण किया। उक्त समयावधि में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में चार उपाध्यक्ष एसके द्विवेदी, राम बहादुर, नरेंद्र कुमार चौधरी व जेसी आदर्श और चार सचिव राजकुमार सचान, नरेन्द्र कुमार, सुभाष चन्द्र उत्तम व आरके सिंह तैनात रहे। इसके अलावा कई अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता तैनात रहे।

रेजिडेंट्स का आरोप है कि अवैध निर्माण कराने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होने के चलते जीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर रेजिडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रेजिडेंट्स के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में डीड आफ डिक्लेयरेशन की प्रति पेश की, जिसके तहत सिर्फ प्रोजेक्ट में सिर्फ 536 फ्लैट बनाने की अनुमति थी।

नियमों को ताक पर रखकर जीडीए अधिकारियों ने आंख बंद कर प्रोजेक्ट की आंशिक कंपाउंडिंग भी कर दी, जो स्वीकृति से ज्यादा फ्लैट बनाने पर नहीं की जा सकती थी। प्रोजेक्ट का कंपलीशन आज तक भी जारी नहीं हुई है। अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद यह मामला फिर से गरमा गया है।

गत बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि जीडीए के रहते 134 अवैध फ्लैट बन गए। यह मामला गंभीर है। जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने जीडीए अधिकारियों को आदेश दिए थे कि विस्तार से पूरे प्रकरण की जांच करें, जिन अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान 134 अवैध फ्लैटों का निर्माण हुआ।

उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह में अदालत में पेश करें। हाईकोर्ट के आदेश पर जीडीए अधिकारियों ने एक्सप्रेस गार्डन प्रोजेक्ट की पूरी फाइल खंगालनी शुरू कर दी गई है। जीडीए ओएसडी सुशील चौबे ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

घर पर अवैध दारू-पार्टी वाले दें ध्यान, नोएडा के फार्म हाउसों में चली शराब तो हुई कार्रवाई; दिल्ली-लखनऊ से घन-घनाए फोन

यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस में रात के अंधेरे में अवैध रूप से आयोजित होने वाली शराब पार्टी पर आबकारी विभाग की नजरें टेढी हुई तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उच्च पदों पर बैठे लोगों के फोन घन-घनाने लगे। विभाग की कार्रवाई जारी रही फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया।

ग्रेटर नोएडा। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस में रात के अंधेरे में अवैध रूप से आयोजित होने वाली शराब पार्टी पर आबकारी विभाग की नजरें टेढी हुई तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उच्च पदों पर बैठे लोगों के फोन घन-घनाने लगे। विभाग की कार्रवाई जारी रही, फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। कार्रवाई का परिणाम विभाग को महज एक माह में एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। यमुना नदी के डूब में सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण किया गया है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाउस तोड़ने की कार्रवाई समय-समय पर की जाती है। अंधेरा होने के साथ ही फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों में रात हसीन होने लगती है। आबकारी विभाग के नियम के तहत शराब पार्टी करने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस की फीस 11 हजार रुपये है। साथ ही पार्टी में प्रदेश के बाहर की शराब का सेवन भी प्रतिबंधित है। पार्टी करने वालों के द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाता था। साथ ही प्रदेश के बाहर की शराब का सेवन किया जाता था। इस कारण आबकारी विभाग को दोहरे राजस्व का नुकसान हो रहा था। विभाग ने कमर कसी, पिछले माह नवंबर में फार्म हाउस में होने वाली पार्टी में जांच के लिए विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई। डूब क्षेत्र में फार्म हाउस का निर्माण बिजनेस मैन व अधिकारियों के रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। फार्म हाउस सुविधाओं से युक्त हैं। आलीशान कमरों के साथ ही पार्टी हाल, स्वीमिंग पूल, अस्तबल व अन्य सुविधाएं हैं। जब कार्रवाई शुरू हुई तो खलबली मच गई।

सदन से 142 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में जमकर बोला हल्ला

संसद में विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कमान सराय स्थित कार्यालय में एकजुट होने के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा कि देश की जनता देख रही है कि विपक्ष जनता की आवाज संसद में उठाना चाहता है। यह सरकार आम जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर देती है। सरकार ने सरकारी नौकरी को खत्म करने का काम किया है। आज बेरोजगारी से पूरे देश का युवा परेशान है। बावजूद इसके यह सरकार आम जनता की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती।

प्रदर्शन में ये नेता रहे शामिल

प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, वरिष्ठ नेता राव वीरेंद्र बिल्लू, पंकज डावर, कुलराज कटारिया, वर्धन यादव, धान सिंह तंवर, पंकज भारद्वाज, पूर्व विधायक रामबीर सिंह, कुलदीप कटारिया, अमित भारद्वाज, प्रदीप खटाना, मनीष खटाना, युवा नेता निशित कटारिया, धर्मेंद्र मिश्रा, सूबे सिंह यादव एडवोकेट, नरेश यादव, सतबीर पहलवान, पर्ल चौधरी, निर्मल यादव, पूजा शर्मा, सुशील भारद्वाज टुल्लर आदि शामिल हुए।

संसद में विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

गुरुग्राम। संसद में विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कमान सराय स्थित कार्यालय में एकजुट होने के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा कि देश की जनता देख रही है कि विपक्ष जनता की आवाज संसद में उठाना चाहता है। यह सरकार आम जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर देती है। सरकार ने सरकारी नौकरी को खत्म करने का काम किया है। आज बेरोजगारी से पूरे देश का युवा परेशान है। बावजूद इसके यह सरकार आम जनता की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती।

रविवार के बाद क्रिसमस पर भी खुले रहेंगे बिजली कार्यालय, बकाया बिल का कर सकेंगे

विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को देखते हुए विद्युत निगम के बिजली बिल काउंटर सोमवार को क्रिसमस को भी खुले रहेंगे। साथ ही अधिशासी अभियंता स्तर तक के कार्यालय भी खुलेंगे। अधिकारियों का भी अवकाश रद रहेगा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंधक निदेशक चैत्रा. बी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। लोग इस दिन बकाया बिजली बिल का भुगतान समेत दूसरे कार्य करा सकेंगे।

नोएडा। विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को देखते हुए विद्युत निगम के बिजली बिल काउंटर सोमवार को क्रिसमस को भी खुले रहेंगे। साथ ही अधिशासी अभियंता स्तर तक के कार्यालय भी खुलेंगे। अधिकारियों का भी अवकाश रद रहेगा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंधक निदेशक चैत्रा. बी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। लोग इस दिन बकाया बिजली बिल का भुगतान समेत दूसरे कार्य करा सकेंगे। इससे पहले एक नवंबर के बाद से प्रत्येक रविवार को भी विद्युत निगम के कार्यालय खुल रहे हैं।

एकमुश्त समाधान योजना के विद्युत निगम की तरफ से बिजली बिल के बकाएदारों को ब्याज पर छूट दी जा रही है। एक नवंबर से चल रही योजना तीन चरणों में शुरू हुई थी। 16 दिसंबर से योजना का अंतिम चरण चल रहा है। यह 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा।

इसके साथ ही बिजली चोरी के मामलों में भी पहली बार 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ऐसे में चोरी के मामले के आरोपित छूट के साथ अपना जुर्माना चुका कर केस खत्म कर सकते हैं।

बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर पिता से ठगी, केस दर्ज

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में रहने वाले महेश चंद से बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में उनके बेटे की प्रयागराज में नौकरी लगाने के नाम पर रुपये लिए गए लेकिन नौकरी नहीं लगवाई गई। उनकी शिकायत पर हरेंद्र और दयाराम पर केस दर्ज किया गया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में रहने वाले महेश चंद से बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में उनके बेटे की प्रयागराज में नौकरी लगाने के नाम पर रुपये लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई गई। उनकी शिकायत पर हरेंद्र और दयाराम पर केस दर्ज किया गया है।

इंडिया गठबंधन सिर्फ बैठकें ही करता रहेगा या इन बैठकों का कुछ परिणाम भी निकलेगा

ललित गर्ग

आज दुनियाभर में लोकतंत्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। भारत में विपक्ष की नकारात्मक स्थितियों के कारण यह संकट ज्यादा बढ़ा है। इसका कारण है विपक्ष से जुड़े संस्थानों, राजनीतिक हस्तियों और लोकतांत्रिक निर्णयों का आधार बनने वाली प्रणालियों पर धीरे-धीरे कम हो रहा भरोसा।

संसदीय अवरोध, विपक्षी दलों के 143 सांसदों के निलम्बन एवं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की घटनाओं से आक्रामक हुए राजनैतिक माहौल के बीच 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के साथ चौथी बार फिर से दिल्ली में एक छत के नीचे आया। बैठक का उद्देश्य था कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग एवं संयोजक के नाम पर सहमति सहित कई मुद्दों पर एक राय कायम करना। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस बैठक में दल भले ही आपस में मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाये। लोकतंत्र की मजबूती के लिये सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों की संकीर्ण सोच, सिद्धान्तविहीन राजनीति एवं सत्ता लालसा ने विपक्ष की राजनीति को नकारा कर दिया है। सोचा गया था कि इंडिया गठबंधन विपक्ष से जुड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी की लौ को फिर से प्रज्ज्वलित कर सकेगा और ऐसी सोच एवं राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करेगा जो वास्तव में लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए हो। लेकिन ऐसा न होना इंडिया गठबंधन की बड़ी असफलता है और आने वाले वर्ष 2024 के लोकसभा में उसकी भूमिका टांय-टांय फिस ही होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में एकजुटता की बातें हवा हो रही हैं। न संयोजक और न ही प्रधानमंत्री और न ही नरेन्द्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़े, के नाम पर सहमति बन पायी है।

आज दुनियाभर में लोकतंत्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। भारत में विपक्ष की नकारात्मक स्थितियों के कारण यह संकट ज्यादा बढ़ा है। इसका कारण है विपक्ष से जुड़े संस्थानों, राजनीतिक हस्तियों और लोकतांत्रिक निर्णयों का आधार बनने वाली प्रणालियों पर धीरे-धीरे कम हो रहा भरोसा। विश्वास का यह संकट तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। आज हमें विपक्षी राजनीतिक तंत्र पर मौलिक विचार मंथन के बाद पुनर्मूल्यांकन कर इन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बदलती हुई सामाजिक एवं राष्ट्रीय जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और सरकार एवं शासन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकें जिसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का नहीं बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का महत्त्व हो।

इंडिया गठबंधन की प्रथम अपेक्षा है कि इससे जुड़े सभी दलों में आपसी सहमति एवं एकजुटता बने। लेकिन चौथी बैठक में ऐसा होता हुई नहीं दिखा। सबसे खास बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की अपील की, लेकिन जिस बात का डर शुरू से था वही हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया, जिससे विपक्षी एकजुटता में सेंध लगी और राजनीतिक माहौल गरमा गया। ममता दीदी ने चाल चलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री/संयोजक पद के लिए रख दिया जबकि इस नाम के लिए नीतीश प्रारंभ से लामबंदी कर रहे थे। खड़गे का नाम सुनते ही ना सिर्फ नीतीश बल्कि नीतीश के नाम के पीछे अपने बेटे तेजस्वी का भविष्य तलाशने वाले लालू यादव भी नाराज हो गए। नाराजगी ऐसी कि दोनों दिग्गज लालू और नीतीश कुमार गठबंधन की बैठक के बीच से ही निकल गए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या गठबंधन में सिर्फ बैठकें होंगी या फिर कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। क्या गठबंधन लोकसभा चुनाव की कोई प्रभावी एवं सार्थक चुनावी प्रक्रिया तय कर पायेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। मोदी के रथ पर सवार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ऐड़ी चोटी का जोड़ तो लगा रही है, लेकिन सभी दल एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कोरा सत्ता के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन लोकतांत्रिक आदर्श के लिए नहीं। ऐसा माना जाता है कि सत्ता समझौतों पर टिकी होती है और आदर्श सिद्धांतों पर। दोनों में संतुलन और सामंजस्य की स्थितियां दुर्लभ होती जा रही हैं। विपक्षी दल चाहे कितनी ही समस्याएं पैदा करते हों, लेकिन अगर वे अलग-अलग मुद्दों से ज्यादा नीतिगत प्रश्नों पर ध्यान दें तो उन्हीं के जरिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी दल सत्ता में आने के लिए गठबंधन तब करता है जब अकेले सरकार बनाने या जीतने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन आदर्शवादी राजनीतिक सोच इसे सत्तामोह और समझौतावाद कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्धांतवादी दलों को किसी से गठजोड़ नहीं करना चाहिए, भले उसका परिणाम राजनीतिक असफलता ही क्यों न हो। लेकिन राजनीति में गठबंधन एक विवशता बनती जा रही है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल में सिद्धान्त एवं मूल्यों की राजनीति करने का माद्दा नहीं उभर पा रहा है।

इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की ताकत बनना चाहिए क्योंकि इसने एकदलीय सत्ता का युग खत्म होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और खर्चीले चुनावों के खतरे के प्रति सचेत होकर गठबंधन की सीख बहुत जल्दी ले ली। लेकिन गठबंधन की बुनियादी सोच को विकसित किये बिना ऐसा करना जल्दबाजी एवं सत्ता मोह का निर्णय ही अधिक प्रतीत हो रहा है जिसका कोई सार्थक परिणाम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही विपक्षी दल सिद्धांत और विचारधारा के बदले आर्थिक विकास और व्यापार-रोजगार जैसे नारों से लोगों को लुभा लें। लेकिन ऐसा करते हुए वे अवसरवाद की पुष्टि और विचारधारा के अवमूल्यन के लिए उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दलों के नेताओं का चरित्र एवं साख भी कोई प्रभावी रंग नहीं दिखा पाती। वे एक दल से दूसरे दल में बेहिचक आते-जाते हैं, पितृदल छोड़ कर नए-नए दल बनाते हैं। यह सब राजनीतिक विचारधारा के अंत का सूचक है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में सिद्धांतों और मूल्यों की बातें मजाक होकर रह गई हैं। बड़ी सोच एवं बड़ी दृष्टि इन विपक्षी दलों में पनप ही नहीं पा रही है। इंडिया गठबंधन में कुछ संभावना बनी थी, लेकिन उसमें भी न तो बड़ी दृष्टि है न देश की सही समझ और न ही बड़ी लड़ाई लड़ने का दम और जीवट दिखाई पड़ता है। अगर वाकई देश को राजनीतिक विनाश के रास्ते से हटा कर सही एवं सकारात्मक रास्ते पर लाना है तो जीवट नेतृत्व की अपेक्षा है। ऐसा विपक्षी नेतृत्व उभरे जिसमें समझ और तप दोनों का समावेश हो। राष्ट्र एवं समाज को विनम्र करने का हथियार मुद्दे या लॉबी नहीं, पद या शोभा नहीं, ईमानदारी है। और यह सब प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ सौदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि राष्ट्र, सरकार, समाज, संस्था व संविधान ईमानदारी से चलते हैं, न कि झूठे दिखावे, आश्वासन एवं वायदों से। दायित्व और उसकी ईमानदारी से निर्वाह करने की अनभिज्ञता संसार में जितनी क्रूर है, उतनी क्रूर मृत्यु भी नहीं होती। मनुष्य हर स्थिति में मनुष्य रहे। अच्छी स्थिति में मनुष्य मनुष्य रहे और बुरी स्थिति में वह मनुष्य नहीं रहे, यह मनुष्यता नहीं, परिस्थिति की गुलामी है।

हमारा विपक्षी नेतृत्व अपने पद की श्रेष्ठता और दायित्व की ईमानदारी को व्यक्तिगत अहम् से ऊपर समझने की प्रवृत्ति को विकसित कर मर्यादित व्यवहार करना सीखें अन्यथा शतरंज की इस बिसात में यदि प्यादा वज़ीर को पीट ले तो आश्चर्य नहीं। बहुत से लोग काफी समय तक दवा के स्थान पर बीमारी ढोना पसन्द करते हैं पर क्या वे जीते जी नष्ट नहीं हो जाते? खीर को ठण्डा करके खाने की बात समझ में आती है पर बासी होने तक ठण्डी करने का क्या अर्थ रह जाता है? लोगों के दिलों को जीतने की राजनीति ही सार्थक परिणाम लाती है, विपक्षी दल यह बात भूल कर कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। विपक्षी दलों को लोगों के विश्वास का उपभोक्ता नहीं अपितु संरक्षक बनना होगा। भारत न केवल अपने आकार के कारण, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और पनपने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है, इन बदलती स्थितियों में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिये विपक्षी दलों को एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी सहभागिता देनी चाहिए।

Royal Enfield Classic 350 कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक में क्या कुछ खास

Royal Enfield Classic 350 कंपनी कई बाइक्स को भी लॉन्च कर चुकी है। क्या आप भी अपने लिए रॉयल एनफील्ड की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम रॉयल एनफील्ड की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक की जानकारी लेकर आए हैं।रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल क्लासिक 350 है। नवंबर 2023 में इस बाइक की कुल 30264 यूनिट्स सेल हुई है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में बुलेट का क्रेज काफी अधिक है। रॉयल एनफील्ड को भारतीय बाजार में सबसे अधिक युवाओं द्वारा पसंद किया जाता है। बुलेट मार्केट में दशकों से ब्रिकी के लिए उपलब्ध है। इस दौरान इस बाइक को कई बार अपडेट भी किया गया है। हालांकि कंपनी कई बाइक्स को भी लॉन्च कर चुकी है। क्या आप भी अपने लिए रॉयल एनफील्ड की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम रॉयल एनफील्ड की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक की जानकारी लेकर आए हैं। चलिए आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देते हैं।

Royal Enfield Classic 350

रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल क्लासिक 350 है। नवंबर 2023 में इस बाइक की कुल 30,264 यूनिट्स सेल हुई है। जो नवंबर 2022 में कुल 26,702 यूनिट्स की सेल हुई थी। इसमें कुल 13.34% प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस ब्रिकी के साथ यह देश में सबसे अधिक बिकने वाली बाइक में से एक है।

Royal Enfield Classic 350 कीमत

भारतीय बाजार में इस बाइक की कीमत 1.93 लाख रुपये से लेकर से 2.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच है। यह सिंगल चैनल एबीएस और ड्यूल चैनल एबीएस के ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। जो 20.2 पीएस और 27 एनएम का पावर आउटपुट जनरेट करती है।

Royal Enfield Classic 350 इंजन

इसमें 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाइक में एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल ओडोमीटर, नेविगेशन, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, पास स्विच, इंजन किल स्विच, बल्ब टाइप टर्न सिग्नल लैंप और हैलोजन हेडलाइट मिलता है।

भारतीय बाजार में इस साल लॉन्च हुई ये दमदार सीएनजी कारें, कीमत 6.55 लाख रुपये से शुरू

Top 6 CNG Cars Launched In 2023 इस साल कई शानदार सीएनजी कारें लॉन्च हुई है। इस खबर के माध्यम से इस साल लॉन्च हुई सीएनजी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। TATA PUNCH CNG भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल में से एक है। इस कार में कुल पांच वेरिएंट - प्योर एडवेंचर एडवेंचर रिदम एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड डैज़ल एस मिलते हैं।

नईदिल्ली। भारतीय बाजार में इस समय सीएनजी कारों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इस साल कई शानदार सीएनजी कारें लॉन्च हुई है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस साल लॉन्च हुई सीएनजी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है।

TATA ALTROZ CNG

टाटा मोटर्स ने मई 2023 में अल्ट्रोड हैचबैक का सीएनजी वर्जन लॉन्च किया है। इसमें नई ट्विन सिलेंडर सीएनजी तकनीक मिलती है। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये कार सनरूफ के साथ आने वाली पहली सीएनजी कार है। इस कार की कीमत 7.55 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

TATA TIAGO और TIGOR CNG

टाटा टियागो हैचबैक और टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान कार की नई ट्विन-सिलेंडर सीएनजी के साथ आने वाली कार है। इस कार की कीमत 6.55 लाख रुपये से 8.20 लाख रुपये के बीच है। वहीं, टिगोर की कीमत 7.80 लाख रुपये से 8.95 लाख रुपये (सभी एक्स-शोरूम) के बीच है।

TATA PUNCH CNG

भारतीय बाजार में ये सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल में से एक है। इस कार में कुल पांच वेरिएंट - प्योर, एडवेंचर, एडवेंचर रिदम, एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड डैज़ल एस मिलते हैं। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 7.10 लाख रुपये, 7.85 लाख रुपये, 8.20 लाख रुपये, 8.85 लाख रुपये और 9.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

MARUTI BREZZA CNG

मार्केट में मारुति सुजुकी ब्रेजा भारत की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये सीएनजी के साथ आती है। इस कार की कीमत 9.24 लाख रुपये से 12.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। इस कार की माइलेज 25.52km/kg की है।

MARUTI GRAND VITARA CNG

मार्केट में मारुति की एक और कार सीएनजी में आती है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी की कीमत 13.05 लाख रुपये से 14.86 लाख रुपये के बीच है। इस कार की माइलेज 26.6 किमी/किलोग्राम है।

स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन लोगों के लिए शानदार मौका, Kawasaki अपने कई मॉडल्स पर दे रही है बंपर छूट

नए साल के मौके पर आप अपने घर पर एक धांसू स्पोर्ट्स बाइक खरीद सकते हैं। टू -व्हीलर बनाने वाली कंपनी Kawasaki दिसंबर 2023 में अपने कई मॉडल्स पर फेस्टिव सीजन की छूट दे रही है। यह ऑफर कंपनी के लाइनअप में कई मॉडल्स पर उपलब्ध है। इसमें Versys 650 adventure tourer से लेकर Ninja 400 तक शामिल है।

नईदिल्ली। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन है और अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि नए साल के मौके पर आप अपने घर पर एक धांसू स्पोर्ट्स बाइक खरीद सकते हैं।

टू -व्हीलर बनाने वाली कंपनी Kawasaki दिसंबर 2023, में अपने कई मॉडल्स पर फेस्टिव सीजन की छूट दे रही है। यह ऑफर कंपनी के लाइनअप में कई मॉडल्स पर उपलब्ध है। इसमें Versys 650 adventure tourer से लेकर Ninja 400 तक शामिल है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

यहां मिल रही पूरे 60 हजार रुपये की छूट

आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी Versys 650 adventure tourer मॉडल पर 20,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 7.77 लाख रुपये है। वहीं इसके ट्विन-सिलेंडर मॉडल बाइक Ninja 650 स्पोर्टबाइक पर 35 हजार रुपये तक की छूट दे रही है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 7.16 लाख रुपये है। इसके अलावा Ninja 400 पर भी 35,000 रुपये की ही छूट मिल रही है इसकी कीमत 5.24 लाख रुपये है। Vulcan S cruiser पर कंपनी 60 हजार रुपये तक की छूट दे रही है। इसकी कीमत 7.10 लाख रुपये है।

न्यू लॉन्च बाइक मचा रही धूम

वाहन निर्माता कंपनी ने इंडिया बाइक वीक में मोस्ट अवेटेड मोटरसाइकिल कावासाकी W175 स्ट्रीट बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसके स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 12 हजार रुपये से अधिक का सस्ता कर दिया है। कावासाकी के नए लॉन्च हुए रेट्रो–क्लासिक वाली मोटरसाइकिल की कीमत 1.35 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है। इस बाइक की डिलीवरी भी इसी महीने से शुरू हो जाएगी। इसमें 177 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है।

इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिल रहे हैं शानदार डिस्काउंट, टू-व्हीलर ईवी पर भी है ऑफर्स की बौछार

साल का अंतिम महीना चल रहा है और ऐसे में ईवी वाहनों पर जमकर ऑफर्स की बौछार हो रही है। ऐसा स्टॉक को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में डीलर और कंपनियों के पास अधिक स्टॉक है तो डिस्काउंट भी ज्यादा ऑफर किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से वाहनों पर ऑफर मिल रहे हैं।

नई दिल्ली। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए खास साबित हो सकता है। क्योंकि दिसंबर महीने में ईवी वाहनों पर जमकर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ऐसा स्टॉक खत्म करने के लिए किया जा रहा है।

पिछले साल की तुलना में डीलर और कंपनियों के पास अधिक स्टॉक है तो डिस्काउंट भी ज्यादा ऑफर किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किन-किन गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल रहे हैं।

Tata Tiago EV

टाटा टियोगो ईवी को सस्ते में खरीदने का अच्छा मौका है। इस ईवी पर 50 हजार रुपये तक के कैश बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। 15 हजार रुपये तक के एक्सचेंज और डीलर ऑफर्स का भी अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है।

Hyundai Kona EV

इस गाड़ी को लेने वाले ग्राहकों को 3 लाख रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। इन बेनिफिट्स में इंश्योरेंस/रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज पर छूट और कम ब्याज दरों पर फाइनेंस जैसे ऑफर मुख्य तौर पर शामिल हैं।

Mahindra XUV400 EV

महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी को दिसंबर के महीने में कम दाम में लेने का मौका है। इस ईवी कार पर 3 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक के कैश बेनिफिट्स ऑफर दिए जा रहे हैं।

Tata Nexon EV Prime और Max पर डिस्काउंट

टाटा नेक्सन ईवी प्राइम और मैक्स के प्री फेसलिफ्ट मॉडल पर डिस्काउंट प्रदान किए जा रहे हैं। ईवी प्राइम पर 1.5 लाख रुपये तक के कैश बेनिफिट और 50,000 रुपये तक के अन्य ऑफर मिल रहे हैं। जबकि मैक्स पर भी प्राइम के समान ऑफर मिल रहे हैं।

टू-व्हीलर ईवी पर मिल रहा डिस्काउंट

साल के अंतिम महीने में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिस्काउंट मिल रहे हैं।

हीरो विदा वी-1- 38,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और एक्सटेंडेड वारंटी जैसे ऑफर शामिल हैं।

एथर- इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 24,000 रुपये के कैश बेनिफिट, बैटरी प्रोटेक्ट वांरटी और अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहे हैं।

बजाज चेतक ईवी- ईएमआई के साथ खरीदने पर 2600 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

सरकार-विपक्ष के टकराव से करोड़ों बर्बाद

योगेंद्र योगी

सांसदों का चुनाव इसीलिए होता है कि संसद में जाकर आमजन की तकलीफों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के लिए रास्ते बनाएं। इसके विपरीत सांसद फिजूल की बहसबाजी में उलझे हैं'

आजादी के बाद से अब तक संसद की कार्यवाही का सबसे कम संचालन होना देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी की हठधर्मिता से देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इससे करदाताओं के गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए हंगामे की भेंट चढ़ गए। देश के जरूरी समस्याओं पर चर्चा करने और उनके समाधान तलाशने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष शत्रुओं की तरह एक-दूसरे को ललकारने में लगे रहे। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग पर शुरू हुए विवाद से कुल 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ। इनमें 112 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद सस्पेंड किए गए हैं। कांग्रेस के 60 (लोकसभा से 43, राज्यसभा से 17), एनसीपी के 4 (लोकसभा से 3, राज्यसभा से 1), डीएमके के 21 (लोकसभा से 16, राज्यसभा से 5), सीपीआई-एम के 5 (लोकसभा से 2, राज्यसभा से 3), सीपीआई के 3 (लोकसभा से 1, राज्यसभा से 2), जेडीयू के 14 (लोकसभा से 11, राज्यसभा से 3), नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 (लोकसभा से), तृणमूल कांग्रेस के 21 (लोकसभा से 13, राज्यसभा से 8), सपा के 4 (लोकसभा से 2, राज्यसभा से 2), बसपा का एक (लोकसभा से), आरजेडी के 2 (राज्यसभा से), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तीन (लोकसभा से), आप का एक (लोकसभा से), केरला कांग्रेस का एक (राज्यसभा से), झामुमो का एक (राज्यसभा से), वीसीके का एक (लोकसभा से) और आरएसपी का एक (लोकसभा से) सांसद हैं। सत्ता पक्ष पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। खड़गे ने कहा कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाह रही है। विपक्ष की आवाज दबा रही है। संसद में बोलना हमारा अधिकार है।

सभापति मामले को जातिगत रंग दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद से विपक्ष के सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय जांच के लिए समिति बनाई गई है और जांच जारी है।

पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए ही उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। बिरला ने विपक्ष के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आ जाना ठीक नहीं है। जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती। सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनका सुरक्षा में चूक के मामले से संबंध नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अहम बिल पास हुए। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता करीब 74 प्रतिशत रही। इस सत्र में विपक्षी दलों की गैर-मौजूदगी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, दूरसंचार विधेयक सहित 18 अहम बिल पारित किए गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। यह पहला मौका नहीं है जब संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे और निलंबन की भेंट चढ़ गया। इससे पहले मणिपुर मामले को लेकर संसद की कार्यवाही में भारी गतिरोध रहा। संसद में सेंध पर गृहमंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग की तरह विपक्ष मणिपुर हिंसा पर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को लेकर अड़ा रहा। मणिपुर मामले को लेकर बार-बार संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई।

विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर संसद में मुद्दे पर चर्चा करने और केंद्र के साथ सहयोग करने को कहा, किन्तु विपक्ष पीएम मोदी के बयान देने पर अड़ा रहा। संसद सेंध और मणिपुर मामलों में विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष ने सुनवाई नहीं की। सत्ता पक्ष का आरोप था कि विपक्ष जानबूझ कर संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसी गतिरोध का परिणाम रहा कि हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और सता पक्ष की तरफ से विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन किया गया। पॉलिसी रिसर्च स्टडीज (पीआरएस) की रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं लोकसभा का यह अंतिम साल है। अब तक इसमें 230 दिन ही कार्यवाही चली है। पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में से, 16वीं लोकसभा में बैठक के दिनों की संख्या सबसे कम (331) थी। कार्यकाल में एक और साल शेष होने और साल में औसतन 58 दिनों की बैठक के साथ, 17वीं लोकसभा वर्ष 1952 के बाद से सबसे कम समय तक चलने वाली लोकसभा बन सकती है। मानसून सत्र से पहले संसद में 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक बजट सत्र चला। लोकसभा में सेशन की कार्यवाही के लिए 133.6 घंटे निर्धारित हैं, लेकिन सदन में मात्र 45.9 घंटे तक ही कार्यवाही चली। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही के लिए 130 घंटे तय हैं, लेकिन यहां मात्र 32.3 घंटे ही कार्यवाही चली। बजट सत्र के फस्ट हाफ में एक भी बिल पास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों की तुलना में इस साल बजट सेशन की कार्यवाही का हाल सबसे बुरा रहा। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल प्रोडक्टिविटी 34 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 24.4 प्रतिशत था। वहीं, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की उत्पादकता महज 24.4 प्रतिशत आंकी। वर्ष 2022 में लोकसभा में कुल 177 घंटे और राज्यसभा में मात्र 127 घंटे ही काम हुआ।

जबकि 2021 में लोकसभा के लिए यह आंकड़ा 131.8 घंटे और राज्यभा में 101 घंटे रहा। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने संसद चलने की लागत 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट बताई। उन्होंने बताया कि इसमें बिजली, पानी, पेट्रोल, खाने का बिल, संसद की सिक्योरिटी, सांसदों की सैलरी-अलाउंस, सिक्योरिटी गार्ड और यहां के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले लोगों को दी जाने वाली सैलरी का खर्च शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में बजट सत्र में केवल छह दिनों में संसद में गतिरोध के कारण 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। संसद में 2021 के गतिरोध से करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के कारण न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई, बल्कि देश को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। देश के मतदाताओं की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स से चलने वाली संसद में कीमती वक्त और करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। दीगर है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी तक बिजली, पानी, सडक़, अस्पताल, परिवहन सेवा, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सांसदों का चुनाव इसीलिए होता है कि संसद में जाकर आमजन की तकलीफों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के लिए रास्ते बनाएं। इसके विपरीत सांसद फिजूल की बहसबाजी में उलझ कर आम लोगों की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं। देश में जब जिम्मेदारी तय करने पर चर्चा की जाती है, तब यह फार्मूला सभी राजनीतिक दलों पर लागू किया जाना चाहिए। इसके अभाव में ऐसी संसदीय परंपराओं के अपमान के साथ जनप्रतिनिधियों पर लगाम लगाना मुश्किल है।

संपादक की कलम से

कोरोना की 'लहर' नहीं

कोरोना वायरस के कुछ मामले जरूर आ रहे हैं, लेकिन यह कोई 'लहर' नहीं है। महामारी की सुनामी नहीं है। जो भयानक मंजर हम देख और झेल चुके हैं, एकदम उसकी वापसी भी नहीं है। वायरस की एक नई नस्ल भारत में भी है-जेएन-वन। यह बीए-2-86 या पिरोला का ही एक और प्रकार है, जो ओमिक्रॉन वायरस के ही प्रकार हैं। उन्हीं की कतार में जेएन-1 है। आज इसके संक्रमण का विस्तार 40 देशों में बताया जा रहा है। हमारे देश में गुरुवार, 21 दिसंबर तक कुल 2669 संक्रमित मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनमें से 2300 से अधिक अकेले केरल में हैं। अभी तक सिर्फ 6 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 केरल में हुई हैं। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब में दर्ज की गई हैं। पिछले दौर में भारत संक्रमण के हजारों मामले रोजाना देख चुका है। कुछ बड़े अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की सांसें ऑक्सीजन की कमी के कारण टूटी थीं। वैसे मंजर की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि वायरस की यह नस्ल उतनी घातक नहीं है। हम अपने पाठकों को आश्वस्त कर सकते हैं कि लॉकडाउन के आसार नगण्य हैं। एक-दूसरे राज्य में आने-जाने पर अभी कोई पाबंदी नहीं है। मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं किया गया है। अलबत्ता इतना आग्रह जरूर किया जा रहा है कि यदि आप भीड़ वाले इलाके में जाएं, तो मास्क पहन लें। यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आप हृदय, लिवर, गुर्दे, मधुमेह आदि बीमारियों के पुराने मरीज हैं, तो भी मास्क पहन कर भीड़-भाड़ वाले बाजार या क्षेत्र में जाएं। कोरोना वायरस को लेकर हम अब कोई ढील नहीं बरत सकते, लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को परामर्श भेजा है कि अस्पतालों में पूरी तैयारियां रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हों। आईसीयू की व्यवस्था चाक-चौबंद हो और मॉक ड्रिल करके देख लें कि तमाम बंदोबस्त हो गए हैं अथवा नहीं। इन परामर्शों से आप चिंतित न हों और दहशत के कोई भी आसार भी न हों। लेकिन इनसे साबित होता है कि कोरोना वायरस अब भी जिंदा है, वायरस कभी नहीं मरते, उनकी नस्लें संक्रमण फैलाती रहती हैं। अमरीका जैसा विकसित देश भी कोरोना-मुक्त नहीं हो पाया, यह वायरस के अस्तित्व के कारण ही है।

वैसे सबसे पहले अगस्त, 2023 में यह वायरस लक्समबर्ग में पाया गया। उसके बाद इंग्लैंड, आइसलैंड, फ्रांस और अमरीका में इसके मामले दर्ज किए गए। इन देशों में जीनोम निगरानी काफी सक्रिय है, लेकिन अन्य वायरस की तुलना में जेएन-1 अप्रभावी है। चिकित्सकों की सलाह है कि जिनमें इम्युनिटी कम है या दबी हुई है, ऐसे बुजुर्ग लोग मास्क से अपना बचाव कर सकते हैं। सांस से संबंधी सभी वायरस, कोरोना समेत, के लिए अच्छी किस्म के मास्क काफी बचाव कर सकते हैं, लेकिन दहशत का कोई कारण नहीं है। सचेत जरूर रहें। ऑमिक्रॉन की जितनी भी नस्लें हैं, वे डेल्टा की तरह संक्रामक नहीं हैं। वे ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकती हैं, लेकिन उनसे मौतें बहुत कम होंगी। चिकित्सक यह भी मानते हैं कि जिन्होंने कोरोना के टीके की दोनों खुराक ली हैं, वे मौजूदा वायरस से भी व्यक्ति का बचाव कर सकती हैं। वे आज भी प्रभावी हैं। सर्दी का मौसम गहराने लगा है। आगे क्रिसमस त्योहार और नववर्ष के समारोह भी हैं। जाहिर है कि उनमें भीड़ जरूर आएगी, लिहाजा उसका बचाव जरूर करें। कहीं ऐसा न हो कि आनंद के उत्सव आपको बीमार ही कर दें। बेशक कोरोना की कोई 'लहर' नहीं है और न ही वायरस घातक है, लेकिन अगले कुछ दिन तक संक्रमण के आंकड़े आपके सामने जरूर आते रहेंगे। उनसे घबराना नहीं है। यह वायरस का सार्वजनिक प्रभाव है। यदि आपको थोड़ा-सा भी बुखार होता है, तो कोरोना के दौर वाला व्यवहार ही करें। खुद को दूसरों से अलग और दूरी पर रखें। बेहतर होगा कि आप मास्क पहनें।

चर्चा

क्या वे 'आतंकी घुसपैठिए' हैं

लोकसभा में घुसपैठ करने वाले क्या आतंकवादी हैं? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अदालत में सरकारी वकील ने ऐसे आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस का भी अंदेशा है कि घुसपैठियों की किसी आतंकी साजिश में भूमिका हो सकती है! यदि किसी भी तरह उनके तार आतंकवाद से जुड़े हैं, तो जांच के निष्कर्ष स्पष्ट कर सकते हैं। यह भी संवेदनशील स्थिति है कि कथित आतंकी संसद की दर्शक-दीर्घा तक पहुंच कर लोकसभा की कार्यवाही के बीच छलांग लगाकर सुरक्षा-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर चुके हैं। क्या अन्य आतंकियों के लिए रास्ता साफ किया जा चुका है? आतंकवाद का कोई निश्चित चेहरा-मोहरा नहीं होता। किसी की गतिविधियों और घुसपैठी करतूतों से ही आतंकवाद की ओर संकेत जाते हैं। चूंकि पुलिस और जांच एजेंसियों ने संसद के घुसपैठियों के खिलाफ 'आतंकवाद रोधी अधिनियम' (यूएपीए) की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, आपराधिक साजिश, देश को तोडने, दंगा फैलाने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने की धाराएं भी लगाई गई हैं, लिहाजा प्रथमद्रष्ट्या यह आतंकवाद का मामला लगता है। आरोपितों के काम-धंधे, पढ़ाई और पृष्ठभूमि को देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता। यूएपीए कठोरतम कानून है, जिसमें फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके तहत जमानत भी असंभव-सी होती है। फिलहाल अदालत ने 7 दिन की रिमांड दी है, जिसे बढ़ाया जाना प्रक्रिया का ही हिस्सा है।

सवाल है कि यदि आरोपित घुसपैठिए आतंकी हैं, तो वे किस संगठन से जुड़े हैं? किसकी साजिश पर उन्होंने लोकसभा में कूदने और धुआं-धुआं करने जैसा हमलावर रुख अपनाया? यदि वे बीते डेढ़ साल से संसद में घुसकर उत्पात मचाने या सनसनी फैलाने की साजिश पर विमर्श कर रहे थे और देश के अलग-अलग शहरों में मुलाकातें कर रहे थे, तो उनके खर्चे कौन उठा रहा था? कौन फंडिंग कर रहा था उन्हें? सवाल कई हैं और जांच के दौरान उन्हें जरूर खंगाला जाएगा, लेकिन वे 'बेचारे', 'बेरोजगार' और 'भूले-भटके नौजवान' नहीं माने जा सकते। जब कश्मीर में आतंकवाद और जेहाद चरम पर थे, तब भी युवा आतंकियों को 'भूले-भटके' करार दिया जाता था, लेकिन अकेले उस आतंकवाद ने ही करीब 45,000 जिंदगियां छीन ली थीं। पंजाब और पूर्वोत्तर के आतंकवाद या उग्रवाद की तो चर्चा हम कर ही नहीं रहे। यदि ऐसे विशेषण देकर विपक्ष इन घुसपैठियों का बचाव करेगा और माफ करने की पैरवी करेगा, तो निश्चित ही देश में आतंकवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। देश में लाखों-करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और औसत परिवार महंगाई के दंश झेल रहा है, तो इसके मायने ये नहीं हैं कि वे संसद पर ही हमला कर दें! यकीनन ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं, लेकिन संसद में घुसपैठ करना तो जघन्य अपराध है। बहरहाल सभी आरोपित सोशल मीडिया पर 'भगत सिंह फैन क्लब' और 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस' ग्रुप से जुड़े हैं। बल्कि उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी बनने का मुगालता पाल लिया है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को 'अतिवादी नक्सल' चित्रित कर उन्होंने एक और अपराध किया है। देश में अब अंग्रेजों की नहीं, हमारी अपनी लोकतांत्रिक सत्ता है। फिर किस पर 'स्मोक कैन' या 'बम' अथवा 'ग्रेनेड' का इस्तेमाल किया जा रहा है? यदि आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं, तो चुनाव आने वाले हैं। उनके खिलाफ जनादेश दिया जा सकता है, लेकिन संसद के खिलाफ साजिश स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे पर क्षुद्र राजनीति करना और बदले में 13 लोकसभा सांसदों को निलंबित करना अच्छा संसदीय आचरण नहीं है। ब

राजेंद्र ठाकुर

नाक में रुई डल जाना

मैंने हिंदी के लिए एक नया मुहावरा गढ़ा है। मुहावरा है- नाक में रुई डल जाना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यह मुहावरा बिल्कुल मौलिक है, और स्वरचित भी। इसका वाक्य में प्रयोग करके भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह प्रयोग है- आजकल के कुछ संस्कारविहीन बच्चे इस ताक में रहते हैं कि कब उनके माता-पिता की नाक में रुई डल जाए

दस जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। आज हिंदी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, और उनके क्या समाधान हैं, इस विषय पर चर्चा तर्कसंगत है। लेकिन इससे पहले मैं इस शुभ अवसर पर अपने नए मुहावरे से परिचित करवाना चाहूंगा। मैंने हिंदी के लिए एक नया मुहावरा गढ़ा है। मुहावरा है- नाक में रुई डल जाना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यह मुहावरा बिल्कुल मौलिक है, और स्वरचित भी। इसका दो वाक्यों में प्रयोग करके भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला प्रयोग है- आजकल के कुछ संस्कारविहीन बच्चे इस ताक में रहते हैं कि कब उनके माता-पिता की नाक में रुई डल जाए। दूसरा प्रयोग है- आतंकवादग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों की नाक में रुई डालने का प्रबंध कर लिया है। हिंदी के इस मुहावरे को अंग्रेजी में इस तरह अनुवादित किया जा सकता है- 'गॉट डाइड'। या फिर यह भी- 'टु पुट कॉटन वूल इन दि नोज ऑफ ए पर्सन।' मुझे आशा है हिंदी जगत को यह मुहावरा स्वीकार्य होगा। आज हिंदी के तीव्र विकास के लिए इसी तरह के और मुहावरे गढने की जरूरत है। अब, विश्व हिंदी दिवस की बात हो जाए। विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से कुछ वर्षों पहले विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अगर हिंदी भाषा को चुनौतियों की बात करें, तो इसे अन्य भाषाओं से चुनौतियां मिल रही हैं। प्रांतीय भाषाओं, अंग्रेजी और उर्दू भाषा से हिंदी को कड़ी चुनौतियां हैं। आज इन भाषाओं में प्रतिस्पर्धा का माहौल है जिसके कारण वे एक-दूसरे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। हिंदी भाषा को दूसरी बड़ी चुनौती मीडिया से उत्पन्न हिंग्लिश भाषा से मिल रही है। मीडिया आज अपने फायदे के लिए हिंग्लिश का प्रचार-प्रसार अधिक कर रहा है। हिंग्लिश ने हिंदी के समक्ष अपनी शुद्धता को बनाए रखने की समस्या उत्पन्न कर दी है। इसके अलावा वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी भाषा को अधिक बल मिल रहा है। इसी के साथ ही सिनेमा ने हिंदी के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की हैं। सिनेमा में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होने के कारण भाषा में अशुद्धता आई है। कुछ विषयों की पुस्तकों का हिंदी में उपलब्ध न होना भी एक दिक्कत है। मशीनी अनुवाद इतना पर्याप्त नहीं है कि पाठकों की मांग को पूरा कर सके। एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह भी है कि शोध और अनुसंधान के लिए हिंदी में शोध अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण शोधार्थी अंग्रेजी में शोधकार्य करना पसंद करते हैं। विज्ञापन बाजार भी हिंदी के लिए दिन-प्रतिदिन चुनौतियां पैदा कर रहा है। एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए अंग्रेजी में विज्ञापन देकर उत्पादों के नाम अंग्रेजी में प्रचारित किए जा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमें हिंदी के सबल और कमजोर पक्षों की समीक्षा करनी है। यह सोचना है कि कैसे हम सब हिंदी के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। हिंदी भाषा के समक्ष उत्पन्न

चुनौतियों से निपटने के उपायों की बात करें तो सबसे पहले हिंदी को व्यवहार और बोलचाल की भाषा बनाने की जरूरत है। अभिव्यक्ति का माध्यम सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा को रोजगार की भाषा बनाना चाहिए।

इसके अलावा हिंदी के माध्यम से युवकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। इसे विज्ञान की भी भाषा बनाया जाए। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा को स्थापित किया गया है। इस तरह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय सभी राज्यों में प्रारंभ किए जाएं। इसके अलावा सरकार को विभिन्न राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध करना चाहिए ताकि विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व विद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना हो सके। अंग्रेजी भाषा पर निर्भरता कम करके भी हिंदी का विकास किया जा सकता है। आज जापान, चीन व कई अन्य राष्ट्र अंग्रेजी ज्ञान के बिना ही आत्मनिर्भर बन गए हैं। साथ ही हिंदी के प्रति लोगों के संकीर्ण और संकुचित नजरिए को बदलने की जरूरत है। हिंदी का प्रचार-प्रसार प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी-सिनेमा का प्रयोग किया जाए। हिंदी में शासकीय और गैर शासकीय कार्यों का संपादन अनिवार्य रूप से किया जाए। हिंदी भाषा को और अधिक समृद्ध बनाया जाए। नए मुहावरे और लोकोक्तियां गढने की जरूरत है।

अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके, हिंदी में अनुवाद को बढ़ावा मिले। क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया जाए, साथ ही विदेशी भाषाओं की रचनाओं के हिंदी में अनुवाद को प्राथमिकता दी जाए। हिंदी को राजभाषा घोषित हुए 74 वर्ष हो गए हैं। आज हिंदी भाषा जनसंपर्क की भाषा बन चुकी है, परंतु राजनीतिक कारणों से आज भी हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई है। यदि भारतवर्ष को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसे हिंदी को कार्य-पद्धति, शिक्षा, ज्ञान, कौशल, व्यापार, मीडिया व बाजार की भाषा बनाना ही होगा। ऐसा किए बिना यह देश न तो संपन्न बन सकता है, न समतामूलक, न ही महाशक्ति और न ही विकसित अर्थव्यवस्था। हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने से पहले उसे जन भाषा बनाना होगा। हिंदी के राजभाषा घोषित होने के बावजूद हमारे देश के कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को ही, आज तक राजभाषा बनाया हुआ है। यह स्थिति हिंदी के प्रतिकूल है। इसे अनुकूल बनाने की सख्त जरूरत है।

चिंतन विचार

बजता है डंका हमारा'

जरूरी नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानों, बाहुबलियों व बदमाशों का ही डंका बजता है। या फिर सीबीआई और ईडी का डंका का बजता है। हम इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं हैं, फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी से हर जगह हमारा डंका बजता है। लोग हमें आकर बताते हैं कि साहब आपका डंका बज रहा है। हम लोगों की बातों में आकर खुश हो जाते हैं कि चलो इस दुनिया में हमारी भी तो कोई प्रतिष्ठा है! हमारे पास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। किसी उद्योग में भागीदारी नहीं है, कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। कोई फार्म हाउस नहीं है। स्विस बैंक में कोई खाता नहीं है। कोई विदेशी पिस्टल नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि हमारे पास प्रतिष्ठा है। जिन्हें नहीं मालूम, उन्हें बताने के लिए हम अपनी जेब में कई तरह के पहचान पत्र रखते हैं जिनमें यह लिखा होता है कि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यानी हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। हम कोई यूं ही यहां पर नहीं रह रहे। पूरी प्रतिष्ठा के साथ रह रहे हैं और प्रतिष्ठा के प्रति हम हमेशा सजग रहते हैं। जब कोई हमें सिर्फ पांच सौ की रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहता है तो हम ताव खाकर कहते हैं कि 'सिर्फ पांच सौ रुपए? आखिर हमें समझ क्या रखा है? हमारी भी तो कोई प्रतिष्ठा है!' हमारी झाड़ सुनकर वही व्यक्ति पांच सौ की बजाय हमें एक हजार रुपए ऑफर करता है तो हम ज्यादा चूं-चड़ाक नहीं करते और यह सोचकर हजार रुपए अपनी जेब में रख लेते हैं कि 'चलो इसने हमारी प्रतिष्ठा का कुछ तो ख्याल रखा है।' हमारी प्रतिष्ठा क्या है, इस बात को पुलिस भी जानती है और बदमाश भी।

लीडर भी जानते हैं और अधिकारी भी। सुबह हमसे पुलिस वाले सलाह लेने आते हैं, दोपहर को बदमाश लोग हमसे सलाह लेने आ जाते हैं और रात होते-होते लीडर लोग सलाह लेने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हमारी प्रतिष्ठा को हमारी पत्नी भी जानती है और उसकी सहेलियां भी। हम अपनी पत्नी के सामने उसकी सहेलियों से आंख नहीं मिलाते ताकि उसकी नजरों में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे और उसकी सहेलियां भी हमें सिर्फ मोबाइल पर ही मैसेज करती हैं और वह भी दफ्तर टाइम में। आखिर उन्हें भी हमारी प्रतिष्ठा बारे मालूम है। हम पत्नी की बात उसकी सहेलियों को नहीं बताते और सहेलियों की बात अपनी पत्नी को नहीं बताते। आखिर बताएं भी काहे को? अपनी प्रतिष्ठा काहे को बिगाड़ें? हमारी प्रतिष्ठा का डंका हमारे ससुराल में भी बजता है। ससुराल वाले जानते हैं कि दामाद को जो दो नंबर की इनकम होती है, उससे वह ससुराल में भी गिफ्ट भिजवा देता है। हमारी प्रतिष्ठा क्या है, यह बात हमारे सहयोगी भी अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि इस समाज में हमारे साहब की भी कोई प्रतिष्ठा है। इससे बढक़र हमारी प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है कि हम पर आज तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। कोई भी जांच एजेंसी हमारे खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश नहीं कर पाई है। जिस-जिस विभाग में हम रहे हैं, उस-उस विभाग में हमारी प्रतिष्ठा का डंका बजता रहा है। अपनी प्रतिष्ठा के बल पर हमने हर विभाग में मौजूद 'संभावना' का दोहन किया है और इस काम में 'नीचे' से हमें पूरा सहयोग मिलता रहा है और 'ऊपर' से पूरा आशीर्वाद। यह हमारी प्रतिष्ठा का ही कमाल है कि हमने अपनी क्यारी में भले ही आज तक कभी टमाटर तक नहीं उगाया, लेकिन हम कृषि विशेषज्ञ के रूप में एक नहीं, पूरे पांच मुल्कों का दौरा करके आए हैं।

गुरमीत बेदी

किसानों के उत्पादों के लिए खुल रहा निर्यात का दरवाजा, मिला सही प्लेटफॉर्म

केले के फूल पत्ते और फल कुछ महीने पहले पहली बार वाराणसी से संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए गए थे। इससे स्थानीय किसानों को केले की अच्छी कीमत मिल गई और विदेशों में बाजार भी खुल गए जहां वे अपने उत्पाद बेच सकते थे। इसके अलावा दिसंबर की शुरुआत में पहली बार पूर्वांचल से आलू खाड़ी राज्यों को निर्यात किया गया था।

नई दिल्ली। कुछ महीने पहले वाराणसी से केले के फूल, पत्ते और फल का पहली बार यूएई में निर्यात किया गया और इससे वहां के किसानों को केले की अच्छी कीमत भी मिली और अपने उत्पाद की बिक्री के लिए विदेश में बाजार भी मिला। दिसंबर की शुरुआत में पूर्वांचल से पहली बार खाड़ी के देशों में आलू का भी निर्यात किया गया।

इस साल अगस्त में अलीगढ़ से गुयाना में आलू भेजा गया था। वैसे ही, इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से केला, गेंदे के फूल, पानी-फल (सिंघाड़ा), अंजीर, बेर, क्रेनबेरी जैसे उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। यह सब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास केंद्र (एपिडा) के प्रयास से संभव हो सका है। तभी पिछले साल भारत ने दुनिया के 102 देशों में फल व सब्जी का निर्यात किया था, जो इस साल बढ़कर 111 हो गया है।

एपिडा के मुताबिक वाराणसी से कई उत्पादों के निर्यात शुरू होने के पीछे बनारस आर्गेनो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी का हाथ है, जिसकी स्थापना एपिडा के सहयोग से की गई। एपिडा के मुताबिक, वहां के ग्रामीण इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाले अभिषेक सिंह ने किसानों की समस्या को लेकर एपिडा से संपर्क किया। किसानों की समस्या पर रिसर्च में पाया गया कि बिचौलिए किसानों के उत्पाद को सही कीमत नहीं देते हैं और उनके उत्पाद को सही प्लेटफार्म भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद कंपनी की स्थापना हुई और एपिडा वहां के किसानों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर लाने लगा और अब नतीजा सामने है।

एपिडा के अधिकारियों के मुताबिक, कृषि निर्यात में बढ़ोतरी के लिए वे लगातार किसान उपज संगठन (एफपीओ) के संपर्क में हैं और उन्हें निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही में पहली बार नीदरलैंड में केले का निर्यात गया है और अगले तीन साल में इस निर्यात को एक अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नीदरलैंड के साथ अन्य यूरोपीय देशों में भी केले के निर्यात की संभावना तलाशी जा रही है।

आम का निर्यात हुआ दोगुना

अमेरिका में अनार व आम के निर्यात के लिए एपिडा ने अहमदाबाद, नासिक, बेंगलुरु जैसी जगहों पर अमेरिकी अधिकारियों का दौरा कराया ताकि किसानों को अपने उत्पादों के निर्यात का प्री-लाइसेंस मिल सके। एपिडा ने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का भी भारत का दौरा कराया और इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2022 के मुकाबले इस वर्ष आम का निर्यात दोगुना हो गया। आर्गेनिक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है।

सरकार अब मादक पेय पदार्थों के निर्यात बढ़ाने में जुटी

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मादक पेय पदार्थों का वैश्विक बाजार 100 अरब डालर का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 32.5 करोड़ डालर की है। मंत्रालय अगले तीन साल में मादक पेय पदार्थों के निर्यात को एक अरब डालर तक ले जाना चाहता है। तभी मंत्रालय के सहयोग से आगामी 8-10 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले इंडस फूड 2024 में भारतीय मादक पेय पदार्थों की नुमाइश की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, इस मेले में 2,500 से अधिक विदेशी तो 5,000 से अधिक देशी खरीदार आ रहे हैं।

स्विगी से ऑर्डर हुई 42.3 लाख रुपये की बिरयानी, इस व्यक्ति ने बनाया रिकॉर्ड

आज के समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। स्विगी ने 2023 का वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा बिरयानी का ऑर्डर हुआ है। विश्व कप के मौके पर लोगों ने बिरयानी के साथ पिज्जा भी काफी ज्यादा ऑर्डर किया है। आइए इस रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नईदिल्ली। हाल ही में स्विगी (Swiggy) ने अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम 'How India Swiggy'd in 2023' है। इस रिपोर्ट में लोगों के पसंद के खाने के साथ कई दिलचस्प कहानी भी है। 2023 में स्विगी पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद बिरयानी आई है। स्विगी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 2.5 सर्विंग्स प्रति सेकेंड की दर से बिरयानी का ऑर्डर दिया।

इस रिपोर्ट में हैदराबाद के एक व्यक्ति के बारे में बताया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हैदराबाद के व्यक्ति ने एक साल में 1,633 बिरयानी ऑर्डर किया है। यह ऑर्डर करी संख्या बिरयानी को लेकर लोगों के प्यार को दर्शाता है।

नॉन-वेज के साथ वेज बिरयानी भी है लोगों की पसंद

स्विगी के रिपोर्ट के अनुसार जहां लोगों को चिकन बिरयानी पसंद आई है। वहीं शाकाहारी लोगों ने वेज-बिरयानी भी ऑर्डर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5.5 चिकन बिरयानी प्लेट के साथ एक वेज बिरयानी भी ऑर्डर हुआ है। 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान भारत-पाकिस्तान का मैच हुआ था। इस मैच के दौरान देश में स्विगी से काफी ऑर्डर हुए है। भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान चंडीगढ़ के एक परिवार ने 70 प्लेट बिरयानी ऑर्डर दिया था।

इस दिन हुआ सबसे ज्यादा ऑर्डर

1 जनवरी 2023 को नए साल के जश्न के मौके पर भी स्विगी को काफी ऑर्डर मिले हैं। स्विगी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नए साल के जश्न के मौके पर 4.3 लाख बिरयानी और 83.5 हजार नूडल्स मिला है। वहीं, 14 मई 2023 को मदर्स डे पर सबसे ज्यादा केक ऑर्डर हुआ है। इसी तरह 30 अगस्त को गुलाब जामुन और 20 अगस्त को बटर नान सबसे ज्यादा ऑर्डर दिया गया है।

19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप के फाइनल में लोगों ने सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किया है। इस दिन एक मिनट में सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किया गया है।

निजी कंपनियों को सीधे आवंटित हो सकते हैं दुर्लभ खनिज भंडार, खनन मंत्रालय ने लिया अहम फैसला

दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को लेकर खनन मंत्रालय द्वारा अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार अब निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों को आसानी से र्लभ खनिजों के भंडार आवंटित किया जाएगा। खनन मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि वर्ष 2021 में ही खनन व खनिज (एमएमडीआर) कानून 1957 में संशोधन किया था।

नई दिल्ली। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके खनन की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इस क्रम में एक अहम फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों को सीधे ही दुर्लभ खनिजों के भंडार आवंटित कर दिया जाएगा।

खनन मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि वर्ष 2021 में ही खनन व खनिज (एमएमडीआर) कानून 1957 में संशोधन किया था जिसके जरिए खनन क्षेत्र की कंपनियों क सूचीबद्ध कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। इसमें सरकारी व निजी दोनों तरह की कंपनियां हो सकती हैं। मार्च, 2022 में इस प्रक्रिया के तहत 16 निजी कंपनियों को खनन क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनियों के तौर पर चिन्हित किया गया था।

17 अगस्त, 2023 को ही केंद्र सरकार ने एमएमडीआर में संशोधन करके ग्रेफाइट, पोटाश, पीजीई, आरईई जैसे 30 खनिज उत्पादों को दुर्लभ खनिज की श्रेणी में डाला था। इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, मोबाइल फोन, सोलर पैनल निर्माण, सेमीकंडक्टर जैसे उद्योग में हो सकेगा। निविदा प्रक्रिया नहीं होने से अब सरकार कंपनियों को चिन्हित करके उन्हें सीधे खनिज भंडार उत्खनन के लिए आवंटित कर सकती है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, 8 दिसंबर तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई बढ़त

परिवहन विशेष न्यूज

8 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समाप्त हफ्ते के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर 2023 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 606.859 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं पिछले हफ्ते की रिपोर्टिंग के अनुसार यह 6.107 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 604.042 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

नईदिल्ली। आरबीआई हर सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को खत्म हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 606.859 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं, पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, कुल भंडार 6.107 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 604.042 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले साल से वैश्विक विकास के कारण दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की रक्षा के लिए पूंजी भंडार को तैनात कर दिया। इसका असर विदेशी भंडार पर देखने को मिला है।

आरबीआई द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार 8 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा संपत्ति 3.089 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 536.699 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना शामिल होता है।

सोने के भंडार में गिरावट

आरबीआई ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 199 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 47.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष आहरण अधिकार 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 18.188 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 4.842 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

सरकार SGB के निवेशकों को दिसंबर और फरवरी में देगी किस्त; सीरीज 3 और 4 के लिए इस दिन से कर सकेंगे निवेश

केंद्र सरकार इस महीने दिसंबर में एसजीबी की एक किस्त जारी करने जा रही है इसके बाद फरवरी में एक और किस्त जारी की जाएगी। इसके अलावा निवेशक सीरीज III एसजीबी के लिए आवेदन की तारीखें 18-22 दिसंबर 2023 हैं और सीरीज IV के लिए 12-16 फरवरी हैं। सरकार की ओर से आरबीआई एसजीबी इश्यू करता है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार इस महीने यानी दिसंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) की एक किस्त जारी करेगी और इसके बाद फरवरी में एक बार फिर दूसरी किस्त जारी करेगी।

इसके अलावा वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया कि वित्त वर्ष 24 के सीरीज III के लिए एसजीबी में सदस्यता की तारीख 18-22 दिसंबर है, जबकि सीरीज IV के लिए सदस्यता की तारीख 12-16 फरवरी 2024 है।

आपको बता दें कि सीरीज I के लिए सदस्यता 19-23 जून के दौरान और सीरीज II के लिए सदस्यता 11-15 सितंबर के दौरान खुली थी।

कौन बेचता है एसजीबी?

एजीबी के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत सरकार की ओर से इश्यू करता है। एसजीबी को शेड्यूल कमर्शियल बैंक (छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), नामित डाकघरों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचा जाता है।

कितनी होती है एसजीबी की प्राइस?

एसजीबी की कीमत रुपये में तय कि जाती है। यह कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) तय करता है जिसका आधार सदस्यता अवधि से पहले सप्ताह के अंतिम तीन वर्किंग डे होता है। 999 शुद्धता वाला सोना जितने पर बंद हुआ है उसके औसत मूल्य से कीमत तय होती है।

ऑनलाइन निवेशकों को सस्ता मिलता है एसजीबी

वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन सदस्यता लेने वाले और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों के लिए एसजीबी का इश्यू प्राइस 50 रुपये प्रति ग्राम कम होगा।

एक व्यक्ति कितना खरीद सकता है एसजीबी?

नियमों के मुताबिक सदस्यता की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट और समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्तीय वर्ष होती है। एसजीबी

वीकेंड पर गाड़ी से घूमने का है प्लान? यहां जानिए क्या है आज पेट्रोल और डीजल का ताजा भाव

नई दिल्ली। नौकरी करने वालों के लिए वीकेंड (शनिवार-रविवार) किसी गोल्ड से कम नहीं है। हफ्ते भर की थकान से राहत और अपने परिवार के साथ समय बीताने का यह सबसे अच्छा दिन होता है। कई लोग तो वीकेंड पर अपने दोस्तों या परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं।

ऐसे में अगर आपके पास कोई वाहन है और आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है ताकी आप उस हिसाब से अपना बजट बना सके।

शुक्रवार को क्रूड ऑयल 1.62 प्रतिशत महंगा होकर 75 .25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था जिसके बाद आज सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने देश के सभी शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित की हैं। ऐसे में अगर आप आज वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत जान लीजिए।

कच्चा तेल हुआ महंगा

आपको बता दें कि कल वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.62 प्रतिशत बढ़कर 75.25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था जिसके बाद आज सुबह तेल कंपनियों ने देश के हर छोटे और बड़े शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत तय की है।

किस शहर में क्या है तेल का भाव?

गुड रिटर्न के मुताबिक आज तेल की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर	पेट्रोल (कीमत रुपये प्रति लीटर)	डीजल (कीमत रुपये प्रति लीटर)
नई दिल्ली	96.72	89.62
कोलकाता	106.03	92.76
नोएडा	96.64	89.82
गुरुग्राम	96.77	89.65
लखनऊ	96.57	89.76

आपराधिक कानून 3 बिल, तारीख पे तारीख अब नहीं

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख पे तारीख के फिल्मी अदालती डायलॉग का गला दबा दिया है।इसके लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 को संसद ने पास कर दिया है। राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये अमल आ जाएगा। इसके अमल में आने के बाद मौजूदा- आईपीसी, सीआरपीसी, और इंडियन एविडेंस कानून एक्ट की जगह इन कानूनों ने जगह बना ली है।

दरअसल मौजूदा आईपीसी में 511 धाराएं हैं। जबकि नए कानून यानि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। महिलाओ और बच्चों से अपराध को धारा -63 से लेकर 99 तक रखा गया है।रेप को 63 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में रेप का प्रावधान है। गैंग रेप को धारा 70 में परिभाषित किया गया है। 12साल तक की बच्ची से रेप में दोषी को फांसी या उम्रकैद हो सकती है। शादी का वायदा कर संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके लिए धारा-69 में प्रावधान किया गया है।ऐसे केस में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

मॉब लिंचिंग:- मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या फिर उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।

संहिता में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में पुलिस की सर्च और जब्ती के वक्त विडियोग्रफी जरूरी है।

7 साल या इससे अधिक की सजा वाले मामले में बिल में ऐसे अपराध स्पॉट पर एफएसएल मोबाइल टीम की विजिट अनिवार्य कर दी गई है।

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में अब परिवार को लिखित में बताना होगा। इसके अलावा आनलाइन भी सूचना देनी होगी।

नए बिल में पुलिस ओर कोर्ट दोनो के लिए जांच ,चार्जशीट दायर करने और फैसला सुनाने का समय भी तय किया गया है।

नए बिल के मुताबिक कोशिश रहेगी कि 3 साल के भीतर फैसला आ जाए। वहीं फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है।

आईपीसी में सेम सैक्स को लेकर प्रावधान था लेकिन वह भारतीय न्याय संहिता में नही है।अगर जबरन ऐसा कोई संबंध बनाता है तो फिर उस मामले में क्या होगा? ये भी बहस का मुद्दा है।

नए बिल में प्रावधान है कि जिसमें अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम जैसे भगौडों पर भी अदालत में ट्रायल चलाया जा सकेगा। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य संहिता इलैक्ट्रानिक और डिजिटल सबूतों के दायरे को बढाता है।यह एविंडेंस भी कागजी रेकार्ड की तरह ही कानूनी तौर से मान्य होंगे।

हिंदुओं की आस्था का केंद्र काशी मथुरा विवाद का हल भी कर्मयोगी मोदी सरकार से ही संभव: परिका सुरेश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रमुख समाजसेवी, धर्मावलंबी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मीडिया सदस्य परिका सुरेश ने अपनी प्रसन्नता को जताते हुए कहा के 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की धर्म अनुरागियों को बेसब्री से इंतजार है। सनातन धर्म अनुरागियों का यह महान सपना पूरा होने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से इस सौभाग्यशाली दिन को देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। देश-विदेश के करोड़ो भगवत भक्त जनों का यह भी सपना है की मथुरा काशी के विवाद को भी यथोचित एवं कानून सम्मत तरीके से खत्म होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा काशी के सर्वे के लिए भी अपनी सहमति दी है। सभी की नजरे यशस्वी कर्म योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि उनके नेतृत्व में इस समस्या का भी हल निकल

आएगा तथा हिंदू धर्म के अनुयायियों को वह दिन देखने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। श्री सुरेश ने कहा की धर्म की रक्षा हम सभी का परम कर्तव्य है तभी धर्म हमारी भी रक्षा करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मथुरा काशी का भी सर्वसम्मति से समाधान निकल आएगा और वह दिन सभी भारतवासियों के लिए अपार गौरव का दिन होगा। श्री सुरेश ने कहा की यशस्वी एवं कर्म योगी प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को याद किया जाएगा तथा उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है।

धर्मेंद्र के बाद गिरिराज और कंग्रस की आपत्ति: कामिया को मंदिर में कैसे ले गए पांडियन? कब होगी कार्यवाही?

मनोरंजन सासमल ओड़िशा

भुबनेस्वर् : हीदी ब्लॉगर कामिया जानी का जगन्नाथ दर्शन विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कामिया के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश और निकास की भाजपा 5टी के अध्यक्ष वी.के. ने लगातार आलोचना की थी। पांडियन को निशाना बनाया जा रहा है. आज इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.गिरिराज ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पोस्ट कर पांडियन की आलोचना की है. उन्होंने लिखा, पुरी मंदिर की पवित्रता को भंग करना बेहद चिंताजनक है. वीके पांडियन द्वारा बीफ प्रमोटर को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना धर्म, इतिहास और आध्यात्मिकता की पूरी तरह से उपेक्षा है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत है.'

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कामिया जानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से माफी की मांग की. पीसीसी अध्यक्ष शरत पटनायक ने माफी की

मांग की. उन्होंने कहा, किसी के आदेश पर, पांडियन कामिया जानी को मंदिर में ले गए। अगर वह मुख्यमंत्री के कहने पर गये थे तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए. शरत पटनायक ने कहा कि भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता विजय पटनायक ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाएगी. उन्होंने कहा, क्या नवीन ने विवादित महिला को महाप्रसाद अभियान के लिए बुलाया था? ऐसे ब्लॉगर को महाप्रसाद का प्रचार करने की क्या जरूरत है?

'न कोई समान विचारधारा न कोई... ', अनुराग ठाकुर ने I.N.D.I अलायंस को बताया भ्रष्ट नेताओं का समूह

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को आईएनडीआईए को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का एक समूह करार दिया जिनकी कोई आम विचारधारा या राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हार की हताशा के कारण गुरुवार को संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र को बाधित किया।

बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को आईएनडीआईए को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का एक समूह करार दिया, जिनकी कोई आम विचारधारा या राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हार की हताशा के कारण गुरुवार को संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र को बाधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता की यह टिप्पणी 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के एक दिन बाद आई है।

अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर उठाया सवाल

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गठबंधन कहां है। वे पंजाब में संघर्ष कर रहे हैं, वे अन्य राज्यों में संघर्ष कर रहे हैं। वे एक स्वर में नहीं बोल सकते। वे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों का एक समूह हैं और एक साथ आए हैं। उनके पास कोई समान विचारधारा नहीं है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम या साझा उम्मीदवार नहीं है। कोई विपक्षी गठबंधन नहीं है।

विपक्षी सांसदों के निलंबन पर क्या बोले ठाकुर?

विपक्षी सांसदों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि उन्हें उन गतिविधियों के लिए निलंबित किया गया था जिन पर अध्यक्ष द्वारा रोक लगाई गई थी। ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अंदर तख्तियां नहीं लाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, तो अध्यक्ष ने सभी से नई परंपराओं के साथ शुरुआत करने का अनुरोध किया। किसी को कागज फाड़कर आसन पर नहीं फेंकना चाहिए और कोई तख्तियां सदन के अंदर नहीं लानी चाहिए।

साथ ही उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद वे हतोत्साहित थे और वे सत्र का बहिष्कार करने का कारण ढूंढ रहे थे। उन्हें आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सत्र आगे बढ़े, कभी भाग लेना नहीं चाहती थी। ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर राजनीति के प्रति गंभीर नहीं होने और भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर खुद का मजाक बनाने का भी आरोप लगाया।

ओडिशा में लौटा कोरोना, कोविड के नए वैरिएंट JN.1 का पता चला

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर् : ओडिशा में फिर लौटा कोरोना! पहली बार कोरोना फैलने का पता चला. केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को कोविड-19 के नए संस्करण, जेएन.1 के प्रसार की रिपोर्ट करने के लिए लिखे जाने के बाद पहले प्रकोप का पता चला है। पिछले 24 घंटों में देश में 423 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 3 हजार 420 हो गई है.जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहीं ओडिशा में लंबे अंतराल के बाद फिर एक पॉजिटिव पाया गया है।

उधर, स्वास्थ्य निदेशक विजय महापात्र ने कहा, "अगर आपमें कोविड के लक्षण हैं तो तुरंत जांच कराएं।" जरूरत पड़ी तो राज्य में जांच केंद्र बढ़ाये जायेंगे. इसीलिए सभी जिला प्रमुख अस्पतालों को निर्देश दिये गये हैं. भले ही मास्क अनिवार्य करने की कोई गाइडलाइन नहीं है, फिर भी लोगों को मास्क पहनना जारी रखना चाहिए। हमें राज्य में निगरानी बढ़ाते हुए सावधान रहना होगा। देशभर में नए वैरिएंट से संक्रमित 98% से ज्यादा लोगों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। बहुत ही कम संक्रमित लोग संक्रमित होते हैं। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट से न घबराने की सलाह दी गई है.

जयहिंद नेशनल पार्टी ने प्रसिद्ध समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ डॉ. राजीव मिश्रा को गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सांसद प्रत्याशी घोषित किया

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। जयहिंद नेशनल पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.राजीव मिश्रा को गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सांसद प्रत्याशी घोषित किया।

अपने केंद्रीय कार्यालय का उदघाटन, श्री श्री 1008 श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी के कर कामलो द्वारा संपन्न हुआ।

डॉ.आशीष श्रीवास्तव (राष्ट्रीय अध्यक्ष) जयहिंद नेशनल पार्टी के गरिमामई उपस्थिति में यह सफल आयोजन हुआ। आचार्य जी का स्वागत माल्यार्पण और शॉल ओढ़ा कर डॉ.आशीष श्रीवास्तव और डॉ.राजीव मिश्रा ने किया।

आचार्य जी ने अपने आशीष वचन से डॉ राजीव मिश्रा एवं पार्टी को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉ. आशीष श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी एक नए विचार धारा से आगे बढ़ रही है और देश में आज भी व्याप्त कुरीतिओं को एक एक करके ख़त्म करने का काम करेगी। आज भी देश में राष्ट्रीय पार्टीयाँ वही 72 वर्ष पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है।जयहिंद नेशनल पार्टी प्रतिमान बदलाव लाने का काम कर रही है और इसके पूर्ण होने तक करती रहेगी।उन्होंने यह भी पुरज़ोर से कहा कि अब देश की राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं और सभी क्षेत्र के भलें लोगों को अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

सांसद प्रत्याशी डॉ.राजीव मिश्रा जी ने सभी का स्वागत किया और अपने संबोधन में सभी को विश्वास दिलाया कि वह जनता के भरोसे पर खरे उतरने का प्रतिदिन काम करेंगे।

पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ और सब ने शपथ ली कि वह अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद रहे डॉ.हिमांशु भटनागर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मेरठ लोकसभा सांसद प्रत्याशी, श्री प्रिंस श्रीवास्तव, अध्यक्ष ,चुनाव समिति, श्री रणजीत मिश्रा ,श्री अजीत दीक्षित, श्री आदित्य सक्सेना, श्री रामेन्द्र दीक्षित, श्री अभिनंदन मिश्रा, महेश रत्नाकर, श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव, ठाकुर युवराज सिंह, डॉ.अखिलेन्द्र खरे, डॉ.विष्णु मोहन श्रीवास्तव, डॉ.फ़ैज, डॉ.शैलेंद्र सरोज, अंकित अग्रवाल, राजन यादव, नरेश राणा, मस्तराम यादव, अनुराग पांडेय, विजेन्द्र यादव, सुनील यादव, किशन राजपूत, सुनील कुमार, अंश मिश्रा, स्तुति, सैफी खान एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023